राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

सुरत–गुजरात,संस्करण शुक्रवार ,10 सितंबर–2021 वर्ष–4,अंक–229 पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ प्रमुख को दिया तीन दिन का समय, अदालत पर मिथ्या आरोप के लिए मांगें माफी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) के अध्यक्ष को अदालत को बदनाम करने और धमकाने के लिए बिना शर्त माफी मांगने के लिए तीन दिन का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कहा कि उन्होंने खुद को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से वंचित कर दिया है और उनके खिलाफ कुछ दंडात्मक कार्रवाई करने का समय आ गया है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ एनजीओ सुराज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में शीर्ष अदालत के 2017 के उस फैसले को रद करने की मांग की गई थी जिसके तहत शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र का बार-बार दुरुपयोग करते हुए कुछ वर्षों में बिना किसी सफलता के 64 जनहित याचिकाएं दायर करने पर उसके खिलाफ 25 लाख रुपये की लागत वसूलने का आदेश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने दहिया को अवमानना नोटिस जारी किया था कि क्यों न उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए और अदालत को बदनाम करने के उनके प्रयास के लिए उन्हें सजा दी जाए। मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने कहा कि अवमानना कार्यवाही में प्रतिवादी और अवमानना करने वाले जमानती वारंट के अनुसरण में पेश हुए हैं। हमने उन्हें विस्तार से सुना है। हमने विद्वान अतिरिक्त सालिसीटर जनरल और सरकारी वकील को भी सुना है। पीठ ने कहा कि पूर्व कार्यवाहियों में सामान्य प्रथा के अनुसार अंत में याचिकाकर्ता ने कहा कि वह बिना शर्त माफी मांगना चाहता है कि उसने जो कुछ कहा है उसे वापस लेने का अनुरोध कर रहा है। हमने उनसे कहा है कि उन्हें तीन दिनों के भीतर अपनी मर्जी से ऐसा करने की स्वतंत्रता है और हम अपना आदेश पारित करते समय इस पर विचार करेंगे।

यूपी में गणेश चतुर्थी

सार्वजनिक स्थल पर स्थापित नहीं कर सकेंगे प्रतिमा, भीड़ इकट्ठा करने पर रहेगी रोक

लखनऊ। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाएं नहीं स्थापित की जा सकेंगी। लोग घरों व मंदिरों में प्रतिमा स्थापित कर पूजन कर सकेंगे। वहीं, अनावश्यक भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी। ये आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अफसरों संग बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए पर लोगों की आस्था को भी यथोचित सम्मान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत समन्वित, नियोजित प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के बीच जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देश के अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है। आज प्रदेश के 33 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है।

विगत दिवस हुई कोविड टेस्टिंग में 66 ज़िलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला। वर्तमान में 199 संक्रमितों का उपचार हो रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि डेंगू व अन्य वायरल बीमारियों के संबंध में जारी प्रदेशव्यापी सर्विलांस कार्यक्रम को प्रभावी बनाया जाए। बुखार व संक्रमण के अन्य लक्षणों के संदिग्ध मरीजों की पहचान की जाए। बुखार, दस्त और डायरिया की दवाइयां वितरित की जाएं। विशेषज्ञ टीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपचार की समस्त व्यवस्था की जाए। बेड, दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था है। फिरोजाबाद, आगरा, कानपुर, मथुरा आदि प्रभावित जनपदों की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए।

अब तक 7 करोड़ 42 लाख से ज्यादा कोविड सैम्पल की जांच

एग्रेसिव ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 07 करोड़ 42 लाख 65 हजार 99 कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटे में हुई 02 लाख 26 हजार 111 सैम्पल टेस्टिंग में 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई। मात्र 09 जनपदों में ही नए मरीज मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत समन्वित, नियोजित प्रयासों से कोरोना की दूसरी लहर पर बने प्रभावी नियंत्रण के बीच जनजीवन तेजी से सामान्य हो रहा है। देश के अन्य राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत बेहतर है। आज प्रदेश के 33 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। विगत दिवस हुई कोविड टेस्टिंग में 66 ज़िलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं मिला।

इसी अवधि में 24 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 16 लाख 86 हजार 441 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। यह सतर्कता और सावधानी बरतने का समय है। थोड़ी सी लापरवाही संक्रमण को बढ़ाने का कारक बन सकती है। कोविड की अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रदेश के 33 जनपदों (अलीगढ़, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली, सिद्धार्थ नगर और सोनभद्र) में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। औसतन हर दिन ढाई लाख से अधिक टेस्ट हो रहें हैं, जबकि पॉजिटिविटी दर 0.01 से भी कम हो गया है और रिकवरी दर 98.7 फीसदी है।

चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द करने के लिए फिर मांगा अधिकार

● आयोग ने की है निष्क्रिय और चुनाव न लड़ने वाली पार्टियों की पहचान। ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद करने का अधिकार दिए जाने के लिए चुनावी कानून में बदलाव पर फिर बल दिया है जो निष्क्रिय हैं और चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने ऐसे राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद करने का अधिकार दिए जाने के लिए चुनावी कानून में बदलाव पर फिर बल दिया है, जो निष्क्रिय हैं और चुनाव भी नहीं लड़ रहे।सूत्रों ने बताया कि आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पिछले हफ्ते कानून मंत्री किरण रिजिजू के साथ विभिन्न चुनावी सुधारों पर चर्चा की थी। इससे जुड़े कई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं। चुनाव आयोग के पास किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने का अधिकार तो है, लेकिन उसे किसी भी पार्टी का पंजीकरण रद करने का अधिकार नहीं है।

किसी पार्टी का पंजीकरण रद करने का अधिकार प्राप्त करने की उसकी मांग वर्षों से कानून मंत्रालय के पास लंबित है।आयोग ने पूर्व में ऐसे राजनीतिक दलों की पहचान की थी, जिन्होंने वर्ष 2005 से चुनाव नहीं लड़ा है। उसने 200 से

अधिक ऐसे दलों को सूची से हटाया भी था। आयोग को संदेह है कि इनमें से अधिकर पार्टियां लोगों से दान स्वीकार करके उनके काले धन को सफेद बनाने में मदद के लिए कागजों पर मौजूद हैं। चुनाव आयोग में करीब 3,000 पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। इनमें से आठ की मान्यता राष्ट्रीय दल के रूप में है, जबकि 53 की मान्यता राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में है।

मिलेगी मजबूती–कैबिनेट ने 56 मालवाहक विमान खरीद की दी मंजूरी

नई दिल्ली। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने वायुसेना के लिए 56 सी-295एमडब्ल्यू मालवाहक विमान खरीदने की मंजूरी दे दी। करार के तहत भारत को स्पेन से चार साल में 16 तैयार विमान मिलेंगे, जबकि शेष 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे जहां सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं वायुसेना को और मजबूती मिलेगी। भारत में 40 मालवाहक विमान को टाटा कंसोर्टियम करार पर हस्ताक्षर होने के बाद 10 साल के अंदर तैयार करेगा। इन सभी विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट लगाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह अपने तरह का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है, जिसमें किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान बनाया जाएगा। ये विमान स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए से खरीदे जाएंगे। साथ ही कहा कि इससे भारतीय विमान निर्माण के इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें देश भर में फैली कई एमएसएमई को इन विमानों के पार्ट बनाने में शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से घरेलू विमान उत्पादन को बढ़ावा मिलने के साथ ही आयात पर निर्भरता में कमी आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। पुराने एवरो विमान का स्थान लेंगे सी-295एमडब्ल्यू एक मालवाहक विमान है और इसकी क्षमता पांच से 10 टन की है। ये वायुसेना के पुराने एवरो विमान का स्थान लेंगे। युद्धक स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और पैरा ड्रॉपिंग के लिए विमान में पीछे की ओर रैम्प गेट बनाया गया है।

बड़े पैमाने पर मिलेंगे रोजगार के अवसर

● रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। उम्मीद है कि 600 उच्च कौशल वाले प्रत्यक्ष रोजगार के अलावा 3000 से ज्यादा परोक्ष और 3000 मध्यम दर्जे के कौशल वाले रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सोशल मीडिया मामला

यूपी सरकार ने ट्विटर के पूर्व एमडी के मामले में जल्द सुनवाई की लगाई गुहार

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से ट्विटर इंडिया के पूर्व प्रबंध निदेशक मनीष माहेश्वरी को जारी एक नोटिस को रद करने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। यह मामला एक यूजर द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट पर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील वीडियो अपलोड करने की जांच से जुड़ा है। जांच के सिलसिले में यूपी पुलिस ने माहेश्वरी को 23 जुलाई को नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए व्यक्तिगत तौर पर पेश होने को कहा था। लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस नोटिस को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया था। यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो सकी है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ

जस्टिस एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदायीय पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। सॉलिसिटर जनरल ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग पीठ से की। पीठ ने उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की जाएगी।

त्योहारों की भीड़ से बढ़ी तीसरी लहर की आशंका, सितंबर–अक्तूबर में जश्न मनाना हो सकता है घातक

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच विशेषज्ञों ने देश में अगले दो महीने के दौरान त्योहारों व अन्य अवसर पर लोगों के जुटने को लेकर चेताया है। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन और बाजारों में भीड़ जुटने से संक्रमण का खतरा पैदा होने की संभावना है। स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों की भीड़ जुटने से परिवार, रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी कोई भी अछूता नहीं रह सकता है। इस दौरान घरेलू काम करने वालों की आवाजाही हो सकती है। सेवा प्रदाता की भी घर में दस्तक संभव है, जिससे आवाजाही पर लगी 'पाबंदी' खत्म हो सकती है। इस तरह की गतिविधियां कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यानी अप्रैल-जून 2021 में टाल दी गई थीं। अगले दो महीनों

के दौरान लोगों के घरों से निकलने और त्योहार या अन्य जश्न वाले कार्यक्रम मनाने को लेकर बड़े पैमान पर लोगों और परिजनों के बीच सर्वे किया गया। देश में इसी हफ्ते गणेश पूजा के साथ त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है। गणेश चतुर्थी के बाद दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली पर्व मनाए जाएंगे। लोगों के एक-दूसरे के साथ मिलने या जुटने से इसी समय तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसी आशंका के बीच लोगों से घरों से निकलने और भीड़ में शामिल होने से लेकर त्योहार मनाने या लोगों के बुलाने समेत कई सवाल और आशंकाओं के बीच सर्वे किया गया। लोकल सर्किल्स के सर्वे में 27000 लोगों की राय ली गई और 12000 से अधिक भारतीय परिवारों को शामिल किया गया। यह सर्वे देशभर के 312 जिलों में किया गया।

80 फीसदी भारतीय एक से दूसरी जगह जाएंगे

सर्वे में पहला सवाल यही था कि क्या आप अगले एक महीने के दौरान किसी और के घर पहुंचेंगे। इनमें से 17 फीसदी ने कहा परिवार या रिश्तेदारों के यहां ठहरेंगे नहीं, 8 फीसदी मित्र, पड़ोसी और साथियों के यहां जाने पर रजामंद दिखे, जबकि 22 फीसदी ने माना कि उनके घरेलू सहायक, सेवा प्रदाता या अन्य से मिलने जा सकते हैं। 80 फीसदी परिवारों में एक या इससे ज्यादा श्रेणी के तहत बाहर जाने के लिए राजी दिखे। इस पर 9392 लोगों ने

59 फीसदी परिजनों, दोस्तों से मिलने को निकलेंगे

इसी तरह 23 फीसदी लोगों ने कहा कि वे परिजनों या रिश्तेदों के यहां नहींरुकेंगे, 11 फीसदी ने कहा दोस्तों, पड़ोसियों या सहयोगियों से मिलेंगे जबकि 5 फीसदी अन्य के यहां जाने को तैयार दिखे।कुल मिलाकर 59 फसदी भारतीय परिवार इस पर तैयार दिखे कि वे परिजनों, दोस्तों या अन्य से मिलने के लिए घर से निकलेंगे।

फजीहत के बाद खुली तालिबान की आंख, सरकार में महिलाओं को शामिल करने का किया वादा; जानें कब तक

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार का ऐलान कर दिया है और 33 सदस्यीय कैबिनेट में एक भी महिला शामिल नहीं है। अफगानिस्तान सरकार में महिलाओं की गैरमौजूदगी को लेकर तालिबान दुनियाभर में आलोचनाओं का सामना कर रहा है। हालांकि, सरकार गठन को लेकर हो रही फजीहत को देखते हुए तालिबान ने सरकार में महिलाओं को शामिल करने का वादा किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबिउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आने वाले दिनों में महिलाओं को भी सरकार में शामिल किया जाएगा।

तालिबानी प्रवक्ता मुजाहिद ने बुधवार को बीएफएमटीवी न्यूज चैनल से कहा, 'यह सरकार अंतरिम है। शरिया कानूनों के सम्मान के लिए महिलाओं हेतु पद होंगे। यह एक शुरुआत है, लेकिन हम महिलाओं के लिए सीटें तलाशेंगे। वे सरकार का हिस्सा हो सकती हैं। यह दूसरे चरण में होगा।' यहां जानना जरूरी है कि काबुल के निवासियों ने देश के शासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग को लेकर काबुल के पश्चिमी भाग दश्ते बारची इलाके में विरोध प्रदर्शन किया।

बता दें कि तालिबान ने मंगलवार को अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार की घोषणा की थी, जिसमें किसी भी महिला को मंत्री के तौर पर शामिल नहीं किया था। इसके बाद से

ही दुनियाभर में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि तालिबान राज में अफगान महिलाओं की स्थिति और बदतर होने वाली है। साथ ही शरिया कानून के सरकार चलाने को लेकर भी कई तरह की आशंकाएं हैं।

90 फीसदी मंत्री केवल पश्तून समुदाय–अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठन भले ही हो चुका हो, लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सभी नस्लीय समूहों को साधने की होगी। नवनियुक्त 33 मंत्रियों में से 90 फीसदी मंत्री केवल पश्तून समुदाय के हैं, जबकि हजारा समुदाय का एक भी मंत्री नहीं है। ताजिक और उज्बेक लोगों को भी पर्याप्त प्रतिनिधत्व नहीं मिला है। सबसे अधिक 42 फीसदी आबादी के साथ पश्तून समुदाय का शुरू से ही अफगान राजनीति में दबदबा रहा है। सुन्नी मुस्लिमों के इस समुदाय के 30 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री अखुंद, उपप्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। इस समुदाय के लोग पश्तो भाषा बोलते हैं। ज्यादातर तालिबान लड़ाके इसी समुदाय से हैं। इसमें हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी का नाम भी शामिल है।

हजारा आबादी 10 फीसदी–देश की आबादी में अल्पसंख्यक हजारा समूह की हिस्सेदारी 10 फीसदी है, लेकिन इसके किसी भी सदस्य को मंत्रिपरिषद में स्थान नहीं मिला है। ये शिया मुस्लिम हैं। यह समूह लंबे समय से हिंसा, दमन और भेदभाव का रहा है शिकार।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

दाग भरी सरकार

अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का एलान कर दिया। जो सरकार बनने जा रही है, उसे लेकर ज्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जो लोग अमेरिका से बीस साल से लड़ रहे थे, वे सत्ता में नहीं आएं और अपनी जगह किन्हीं दूसरे नेताओं को सत्ता संभालने का मौका दें, यह कैसे संभव होता? जो लोग बेहतर या साफ-सुथरी या बेदाग सरकार की उम्मीद कर रहे थे, उनके भोलेपन को जमीनी जवाब मिल चुका है। तालिबान की समर्थक आईएस हो या आईएसआई, दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि अभी तक के लड़ाकू नेतृत्व को हटाकर उदार नेतृत्व की तलाश की जाए। सत्ता परिवर्तन के आधुनिक युग में अगर मध्ययुग अपनी बर्बरता के साथ कूद आया है, तो उसे एक हद तक व्यवहार लायक बनाए रखने में ही भलाई है। विरोध तो तब करना चाहिए था, जब अमेरिका ने इन्हीं लोगों में कथित अच्छा तालिबान देखा था और सत्ता हस्तांतरण की दोहा वार्ता शुरू हुई थी। अब जो भी सरकार जैसे भी वहां बनेगी, उस सरकार को मान्यता भले न दी जाए, लेकिन कमोबेश महत्व तो देना पड़ेगा।

यह हमारे समय का स्याह सच है कि तालिबान की अंतरिम सरकार में कम से कम 14 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकी सूची में रहे हैं। प्रधानमंत्री घोषित मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, उनके दोनों डिप्टी और गृह मंत्री भी सूची में शामिल हैं। इनामी आतंकी सिराजुद्दीन को गृह मंत्री बनाया गया है, तो उनके चाचा हक्कानी को शरणार्थियों की जिम्मेदारी दी गई है। जो लोग सरकार संभालेंगे, उनके नाम दुनिया आगे उनके काम के मुताबिक जानेगी, लेकिन फिलहाल यह जान लेना जरूरी है कि एक सरकार बन रही है, जिसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तक प्रतिबंधित सूची में रहे हैं। अंतरिम कैबिनेट के तमाम 33 सदस्यों को लेकर दुनिया में चिंता जाहिर की जा रही है। दरअसल, यही लोग थे, जो अमेरिकी सेना और अफगानियों पर छिपकर आतंकी हमले करते थे, तो यह सवाल लोगों के दिमाग में स्वत- आएगा कि क्या इन लोगों की आदत रातोंरात छूट जाएगी। इन नए नेताओं को अपने स्थापित चरित्र से अलग तमाम अफगानियों को साथ लेकर चलते हुए दुनिया को दिखाना पड़ेगा। इस सरकार में कोई महिला नहीं है, तो चिंता और बढ़ जाती है।

चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी सावधान रहना होगा। क्या ये दोनों देश तालिबान की नई सरकार को व्यावहारिक बना पाएंगे? हालांकि, एक बड़ी चिंता यह भी है कि तालिबान भी एकमत नहीं हैं और पूरे अफगानिस्तान में उनकी तूती नहीं बोलती है। पंजशीर घाटी में संघर्ष जारी है, वहां से अलग सरकार के गठन की खबर भी आ रही है। पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ विद्रोही गुट का नेतृत्व कर रहे अहमद मसूद की तरफ से कहा गया है कि हम यहां एक वैध और ट्रांजिशनल प्रजातांत्रिक सरकार बनाएंगे। यह अपने आप में खुशी की बात है कि अफगानिस्तान में कोई प्रजातंत्र के बारे में सोच रहा है, पर इस सोच का सामना संगीनों से है। अफगानिस्तान में स्थिर सरकार के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। किसी भी देश को वाजिब वैधता उसकी सरकार के व्यवहार से हासिल होती है। फिलहाल, दुनिया के तमाम आशावादी लोग तो उस मुल्ला अखुंद से भी उम्मीद रखेंगे, जो बामियान के बुद्ध को तोप से उड़ाने में शामिल रहे हैं।

बसपा का ब्राह्मण राग

राजनीति में न तो मुद्दे स्थायी होते हैं, न विचारधारा। देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से ये बदलते रहते हैं। एक वक्त था जब बसपा का नारा बहुजन समाज को ध्यान में रखकर लगाया जाता था अब वक्त बदल चुका है सो बसपा की राजनीति ने भी करवट ली है। सालों बाद फिर से बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला के तहत ब्राह्मण समाज की अहमियत समझी है और इन्हें किसी भी कीमत पर अपने पाले में करना चाहती है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट महज 11-12 फीसद ही हैं, इसके बावजूद बसपा को लगता है कि ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज है, और इस बार चुनाव में कमल का साथ नहीं देगा। ब्राह्मण समाज के भाजपा के प्रति गुस्से का फायदा बसपा उठाना चाहती है और इसीलिए पार्टी ने पूरे प्रदेश में ब्राह्मण सम्मेलन-जिसका नाम बदलकर प्रबुद्ध सम्मेलन किया गया-का आयोजन किया और ब्राह्मण हित की बात कह रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि ब्राह्मणों के प्रति भाजपा और बसपा ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस वर्ग को फायदे के तौर पर देख रही हैं। अतीत के पन्ने पलटें तो मालूम पड़ेगा कि 2007 में भी बसपा ने इसी तरह की सोशल इंजीनियरिंग से सत्ता हासिल की थी। मायावती को यह इल्म है कि उनका कोर वोटर दलित उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस गणित से दलित, ब्राह्मण और अल्पसंख्यक वोट उनकी झोली में आएंगे तो सत्ता भी स्वाभाविक रूप से उन्हीं के पास पहुंचेगी। वैसे बात दीगर है कि मायावती ने हाल के वर्षों में न तो दलितों की आवाज उठाई न अल्पसंख्यकों का सहारा बन सकीं। अपनी अलग शैली की राजनीति के लिए जानी जाने वाली मायावती का यह सियासी गुणा-गणित कितना फायदेमंद रहेगा, देखना दिलचस्प होगा। हां, भाजपा को अब नये सिरे से अपनी राजनीतिक गोटियां चलनी होंगी। ब्राह्मण वोटर भले यादव व मुस्लिम वोटर के मुकाबले संख्या में कम हैं, मगर सरकार बनाने और बिगाड़ने की ताकत जरूर रखते हैं। यही वजह है कि प्रदेश के सियासी रण में उतरने वाली हरेक राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करने को मजबूर है। मायावती के लिए निस्संदेह 2022 का चुनाव उनके वजूद से जुड़ा है लिहाजा उनके हर दांव पर नजर रखनी होगी।

कटाक्ष/ सहीराम

पहले क्या और बाद क्या

देखिए, कायदे से तो मोनेटाइजेशन पहले होना चाहिए था और डिमोनेटाइजेशन बाद में। पर अपने यहां डिमोनेटाइजेशन पहले हुआ और मोनेटाइजेशन बाद में। लेकिन इसे उल्टी गंगा बहना नहीं कहा जा सकता। यह तो लीक से हटकर चलने का मामला है और इसलिए इस पर गर्व भी किया जा सकता है कि लीक छोड़ तीनों चलें शायर, सिंह, सपूत। वैसे जिन सरकारी कंपनियों या संपत्तियों का अब मोनेटाइजेशन किया जा रहा है उनका बिकना तो तब भी नहीं रुका था, बस नाम दूसरा था। तो भैया नाम में क्या रखा है काम तो तब भी यही हो रहा था।

अच्छी बात यह हुई कि डिमोनेटाइजेशन पहले हो गया तो मोनेटाइजेशन में आसानी हो गई। हालांकि डिमोनेटाइजेशन के वक्त बैंकों के बाहर जो लाइनें लगती थीं वैसी मोनेटाइजेशन के लिए नहीं लग रहीं। सरकार मोनेटाइजेशन के लिए अपनी कंपनियों को इस तरह लिए बैठी है, जैसे बाजार में दुकानदार अपना सामान लिए बैठे हैं। ग्राहक न बाजार में नजर आ रहे हैं और न ही कोई सरकार के पास नोटों की थैलियां लेकर पंहुच रहा है। हो सकता है कि नोटों की थैलियां अभी भी विधायकों के लिए सुरक्षित रखी गई हों। देखना कहां-कहां की सरकारें हिल रही हैं। लेकिन सरकारों को हिलाने की बात कहना अभी ठीक नहीं है। क्योंकि अभी तो सरकारें हिलाने का सारा क्रेडिट किसान ले जाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है भैया कि सरकार हिलकर नहीं दे रही। जमीं जुबंद न जुबंद गुल मोहम्मद की तरह। इसे सरकार की संवेदनहीनता नहीं, स्थायित्व कहा जा सकता है। सरकार पर नेतृत्व की मजबूत पकड़ कहा जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि सरकार पर तो पता नहीं कितनी मजबूत पकड़ है, लेकिन लठ पर पकड़ काफी मजबूत है। इतनी कि लठ उठ जाए तो सिर तोड़े बिना नहीं रहता। खैर, हिल तो किसान भी नहीं रहे। सिर तुड़वा कर भी नहीं। बल्कि उनका सिर तो दिनों दिन तनता ही जा रहा है। झंडा ऊंचा रहे कि तरह उनका सिर भी बुलंद है। छप्पन इंच की छाती का तो आजकल बेशक, कोई जिक्र न होता हो, लेकिन किसानों के दम-खम का जरूर हो रहा है। कायदे से तो कृषि कानून भी पहले बनने चाहिए थे और सेठों के गोदाम बाद में। पर यहां भी मामला लीक से हटकर ही रहा। बस दिक्कत यही है जी कि लीक से भटकने पर रास्ता भूलने का खतरा रहता है।

खेती पर भारी पड़ता यह टकराव

वाई के अलघ

महापंचायतों के साथ किसान आंदोलन भी फिर से गति पकड़ने लगा है। जहां-जहां महापंचायत हो रही है, वहां-वहां किसान कहीं अधिक मुखर तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मूलत: एक ही मांग है, केंद्र सरकार जबरन उन पर नए कृषि कानून न लगाए। इसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस आंदोलन के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क दिए जा चुके हैं, मगर कुछ अन्य बातें भी हैं, जिन पर गौर किया जाना चाहिए।

यह तो अच्छी पहल है कि हरियाणा सरकार ने उस अधिकारी का तबादला कर दिया है, जिसने किसानों के सिर फोड़ने की बात कही थी। लेकिन असली मुद्दे की बात यही है कि जिन तीन कृषि विधेयकों पर संसद की मुहर लग चुकी है, और वे कानून बन चुके हैं, उनको फिलहाल लागू नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि अभी महामारी का वक्त है और यह समय विशेषकर किसानों के लिए काफी मुश्किल भरा है।

किसानों की तकलीफ का एक निजी अनुभव साझा करता हूं। महामारी के दौरान आवाजाही बंद हो जाने से व्यापार या तो संभव नहीं हो पाता या फिर काफी कठिन होता है। मेरी पत्नी पहले सुबह की सैर के वक्त ही फल-सब्जी ले आया करती थीं, मगर आजकल वह इसके लिए अहले सुबह नहीं, बल्कि कुछ देर से बाहर निकलती हैं। आखिर क्यों? दरअसल, जो किसान अहमदाबाद जिले से सुबह चार बजे अपनी गाड़ी में फल-सब्जी लेकर मुख्य बाजारों में आया करते थे, वे रात्रिकालीन कर्फ्यू के कारण सुबह छह बजे के बाद घर से निकलते हैं। नतीजतन, न सिर्फ उनके उत्पाद कम बिकते हैं, बल्कि वे बहुत दूर तक अपनी सब्जियां भी नहीं बेच पाते, क्योंकि दूर जाते-जाते दोपहर चढ़ आती है और फिर सब्जियां खराब होने लगती हैं। पहले अहले सुबह निकल जाने के कारण ऐसा नहीं होता था। और यह परेशानी सिर्फ अहमदाबाद जिले में नहीं है। अभी मेहसाणा से नवसारी 'मिल्क ट्रेन' भी नहीं चल रही है, और नासिक-मुंबई के बीच फलों के ट्रक भी नहीं दौड़ रहे। मेरा मानना है कि ऐसी परेशानियों से देश भर के किसान प्रभावित हो रहे हैं।

> किसानों के इस लंबे आंदोलन और सरकार की उदासीनता का सबसे अधिक नुकसान कृषि को हो रहा है, और परोक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़ी कंपनियों के मुश्किलों में रहने के कारण रोजगार विकास दर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है।

इस संदर्भ में देखें, तो कानून में जो बात कही गई है कि किसान कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी) नहीं जाते, सही जान पड़ती है। वाकई, जहां किसान जाते हैं, उनको ही बाजार माना जाना चाहिए। इसलिए, ये कानून मूलत: किसानों की मदद ही करेंगे। फिर भी, जबरन इनको लागू करने का कोई तुक नहीं है। किसानों से सरकार को बात करनी चाहिए। वार्ता ही नहीं, उन्हें यह गारंटी देनी चाहिए कि उनकी शिकायतों पर गौर किया जाएगा। आखिरकार, इस तथ्य से भला कोई कैसे इनकार कर सकता है कि संसद सत्र के आखिरी दिन बिना किसी सार्थक बहस के कृषि विधेयक को पारित कर दिया गया था।

देखा जाए, तो सरकार ने एक और गलती की। उसने न सिर्फ आनन-फानन में ये विधेयक पारित किए, बल्कि उनको लागू करने में भी जल्दबाजी की। इससे उसके खिलाफ और ज्यादा माहौल बन गया। ऐसा संदेश गया कि कुछ न कुछ अंदरूनी बात तो है कि सरकार इन कानूनों को बिना बहस के और इतनी जल्दबाजी में लागू करने जा रही है। इसलिए समाधान की यदि बात करें, तो सरकार को फिलहाल जल्दबाजी से बचना चाहिए। किसानों को यह भरोसा देना चाहिए कि अभी इन कानूनों को टाल दिया जाएगा और अगले साल पर्याप्त बहस के बाद ही इनको लागू किया जाएगा। उनको यह भी समझाया जाना चाहिए कि कानून उनके हित में है और जरूरत के मुताबिक इनमें कुछ बदलाव भी किए जा सकते हैं। हां, मारपीट या झगड़े-फसाद से इस मसले का हल कतई नहीं निकलेगा। वैसे भी, भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों से मारपीट इसका ध्येय नहीं हो सकता।

यहां मुझे रमेश चांद याद आ रहे हैं। वह नीति आयोग के सदस्य हैं। उन्होंने बाकायदा एक शोधपत्र तैयार किया है कि आखिर किस तरह से इन कानूनों को लागू करना चाहिए, ताकि इनका अपेक्षित लाभ हासिल किया जा सके। अपने शोधपत्र में उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे इन कृषि सुधारों का फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा। संभव हो, तो उनके अध्ययन पर विचार-विमर्श होना चाहिए, ताकि किसान और सरकार के टकराव में बीच का कोई रास्ता निकल सके।

दिक्कत यह है कि इस तनातनी में हम कृषि के वास्तविक संकट को नजरंदाज कर रहे हैं। मसलन, इस बार खरीफ फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अमूमन बारिश अगस्त के महीने में होती थी। सरकार की तरफ से किसानों को नए बीज देने, उन्हें क्रेडिट मुहैया कराने अथवा अन्य राहत देने की घोषणाएं भी की जाती थीं। मगर इस साल सितंबर महीने में अप्रत्याशित रूप से तेज बारिश हो रही है, और सरकार उदासीन है। जून-जुलाई में बोई गई फसलें बिल्कुल तैयार होने को थीं, लेकिन अब वे जमीन पर लोटने लगी हैं। साफ है, खरीफ के इस नुकसान का असर भारतीय कृषि पर पड़ेगा। रबी की फसलें अच्छी होने के बावजूद 'एग्रीकल्चर आउटपुट' कम रहेगा। लेकिन, इस गंभीर पहलू पर कोई बात करने को तैयार नहीं।

जाहिर है, किसानों के इस लंबे आंदोलन और सरकार की उदासीनता का सबसे अधिक नुकसान कृषि को हो रहा है, और परोक्ष रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि से जुड़ी कंपनियों के मुश्किलों में रहने के कारण रोजगार विकास दर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। हालांकि, अब भी मौका है। सरकार पहल करे और अपना हाथ बढ़ाए। किसानों से बिना शर्त बातचीत होनी ही चाहिए। मेरे शिक्षक प्रोफेसर लॉरेंस क्लेन ने, जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता थे, मुझे सिखाया था कि अर्थशास्त्र के कानूनों को यदि बिना अक्ल के इस्तेमाल किया जाएगा, तो अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। मौजूदा हालात भी कुछ ऐसे ही हैं। अभी सोच-समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। किसानों और सरकार के बीच यह टकराव अब और लंबा नहीं खिंचना चाहिए। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिमालय दिवस

पारिस्थितिकीय संतुलन में सुरक्षित भविष्य

ज्ञानेन्द्र रावत

आज एशिया की जल मीनार के रूप में विख्यात हिमालयी पर्वत श्रृंखला का अस्तित्व खतरे में है। जबकि भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान समेत इन आठ देशों की जलवायु, जैव-विविधता और पारिस्थितिकी के मामले में एशिया की इस जल मीनार पर निर्भरता जगजाहिर है। यह समूचा क्षेत्र आपदाओं और देशों के सत्ता व क्षेत्र पर प्रभुत्व बनाये रखने हेतु होने वाले संघर्षों का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र भी है। गौरतलब है कि हिन्दुकुश हिमालयी पर्वत श्रृंखला के नाम से विख्यात इस पर्वत श्रृंखला पर इन देशों की लगभग 24 करोड़ से भी अधिक आबादी की आजीविका का भविष्य निर्भर है। और तो और लगभग 19 करोड़ से ज्यादा आबादी को यह पर्वत श्रृंखला पानी और मिट्टी जैसी मूलभूत प्राकृतिक संपदा से संपृक्त करती है। लेकिन विडम्बना है कि इस सबके बावजूद इस क्षेत्र में खाद्य और पोषण सम्बंधी अपर्याप्तता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। असलियत यह है कि हिमालयी क्षेत्र की तकरीब 30 फीसदी आबादी खाद्य असुरक्षा और 50 फीसदी से अधिक महिलाएं और बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल यह पर्वत श्रृंखला इस समूचे क्षेत्र की नाड़ी है। यदि यही बिगड़ी रही तो इस क्षेत्र की खुशहाली की कल्पना ही बेमानी होगी।

देखा जाये तो तिब्बत के पठार तथा तकरीबन 3500 किलोमीटर में फैली यह पर्वत श्रृंखला ध्रुवों की तर्ज पर बर्फ का विशाल भंडार होने के कारण थर्ड पोल के नाम से जानी जाती है। यह मध्य एशिया का उच्च पहाड़ी इलाका है। इसमें 42 लाख वर्ग किलोमीटर हिन्दुकुश, कराकोरम का और हिमालयी इलाका शामिल है जो उक्त आठ देशों में फैला हुआ है। संयुक्त रूप से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बाद दुनिया का साफ पानी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। यहीं से दुनिया की दस प्रमुख नदियों यथा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावती, सलवान, मीकांग, यंगत्जे, यलो, अमदुरिया और तारिम का उद?गम हुआ है। यह सदियों से अपने कछार जो मुख्यत: मोटे तौर पर पठारी, तीखे तथा खड़े पहाड़ी व कम ढाल वाले मैदानी इलाकों में हैं, उक्त देशों के अलावा थाईलैंड, वियतनाम, कम्बोडिया और लाओस तक फैले हुए हैं, के अंतर्गत रहने-बसने वाले तकरीब 24 फीसदी लोगों को जल बिजली परियोजनाओं के जरिये स्वच्छ पानी, पर्यावरण तथा आजीविका के अवसर मुहैया कराती रही हैं। खासियत यह कि इन नदियों के बेसिन में 200 करोड़ के करीब आबादी वास करती है। यह इलाका पारिस्थितिकी का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसमें जैव-विविधता के चार बड़े हॉटस्पाट हैं। गौरतलब यह है कि इसकी पहचान दुनिया के सबसे बड़े पर्वत समूह, सबसे ऊंची चोटियां, सबसे जुदा लोक संस्कृति, भिन्न-भिन्न धार्मिक मान्यताओं, भाषाओं, रीति-रिवाजों, सबसे जुदा फ्लोरा-फौना और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इलाके के रूप में होती है। लेकिन बीते कुछेक बरसों से इतनी संपदाओं-विशिष्टताओं वाला यह इलाका जैव-विविधता, आजीविका, ऊर्जा, भोजन और पानी के संकट से जूझ रहा है। इस संकट में मानवीय हस्तक्षेप की अहम भूमिका है। इस इलाके की तबाही के कारणों में अहम है इस पर्वतीय इलाकों के जंगलों की बेतहाशा कटाई, पर्यटन में बढ़ोतरी और बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय संसाधनों का बेदर्दी से इस्तेमाल। इसके चलते गरीबी बढ़ी, आम जीवन दूभर हुआ, पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित हुआ और आजीविका के संकट के कारण लोग पलायन को विवश हुए। खाद्य असुरक्षा और बढ़ते कुपोषण के चलते अब यह संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका खुलासा नेपाल की राजधानी काठमांडू में चार दशक से सक्रिय 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 2013 से 2017 के बीच विस्तृत अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में किया है।

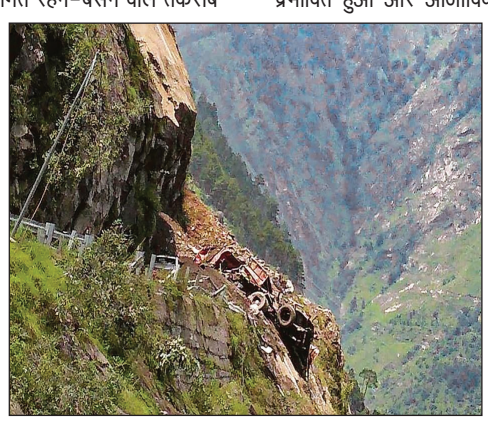

संगठन के सम्मेलन में इस बात पर सहमति व्यक्त की कि जलवायु परिवर्तन, विकास परियोजनाओं, जंगलों की बेतहाशा कटाई और कोविड महामारी से यह क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि जंगलों की कटाई और विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन से पहले बहुत ही बारीकी से परीक्षण किया जाये। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए सभी देश एकजुट हो सकते हैं यदि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान की सरकारें अपने मंत्रियों और प्रतिनिधियों द्वारा अक्तूबर, 2020 में हुए शिखर सम्मेलन में किए गए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। हालांकि इन देशों के पूर्व और वर्तमान तथा अफगान संकट के मौजूदा तनावों को देखते हुए ऐसा होना आसान नहीं लगता।

दरअसल, सम्मेलन में शामिल देशों ने स्वीकार किया कि हिंदुकुश के पहाड़ी क्षेत्र में जलवायु और आपदा रोधी समुदाय विकसित करने के लिए लोगों को प्रशिक्षित करने की और जलवायु परिवर्तन पर एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक समृद्ध, शांतिपूर्ण और गरीबी मुक्त हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र की परिकल्पना की गई है, जहां पर भोजन, ऊर्जा और पानी की कमी न हो और यहां के स्थानीय लोग आत्मनिर्भर हो सकें।

संगठन के उपमहानिदेशक एकलव्य शर्मा कहते हैं, 'वर्तमान में हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का एक हॉटस्पॉट है और इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इससे बुरी तरह प्रभावित हैं। कई आपदाएं और संघर्ष इन देशों की सीमाओं पर होते रहते हैं। अगर सरकारें पर्यावरण संरक्षण, लचीला और समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक साथ ठोस कार्रवाई करें तो हम जलवायु परिवर्तन और अन्य नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक रोक सकते हैं।'

दरअसल जरूरी है कि साल 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को 1.5 डिग्री के लक्ष्य तक बनाए रखने के लिए सभी स्तरों पर ठोस कार्रवाई हो। सतत विकास लक्ष्यों और पर्वतीय प्राथमिकताओं की प्राप्ति हेतु त्वरित कार्रवाई हो। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रति लचीलापन बढ़ाने, जैव-विविधता की हानि और भूमि क्षरण को कम करने के लिए ठोस उपाय किए जाएं और सभी देश संबंधित क्षेत्रीय डाटा और सूचनाओं को आपस में साझा करें ताकि उचित नीतियां बन सकें।

कुपोषण

कैंसर का बड़ा कारण

डॉ. दिव्या चौधरी

कैंसर के कारणों की पड़ताल और उपचार के विमर्श में पोषण का पक्ष हमारी दृष्टि से अक्सर ओझल हो जाता है। हालांकि अधिकतर शोधों में यह निष्कर्ष सामने आ चुका है कि 30-60 फीसदी कैंसर रोगी पहले कुपोषण के शिकार रह चुके होते हैं। यहां तक कि कैंसर से होने वाली 80 फीसदी मौतें भी कुपोषित रोगियों की ही होती हैं। कह सकते हैं कि कैंसर का कारण भी कुपोषण है और कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स यानी दुष्प्रभाव के रूप में भी रोगी कुपोषण का शिकार होता है। वक्त रहते इसकी पहचान और निदान, दोनों जरूरी हैं।

कैंसर के निदान में कुपोषण का पक्ष नजरअंदाज करने से उपचार प्रभावी नहीं हो सकता है। कुपोषण के कारण कैंसर के इलाज में काफी देरी होती है, और रोगी अस्पताल में काफी दिनों तक रहने के लिए मजबूर हो जाता है। यहां तक कि शरीर के विषैले स्राव भी ज्यादा प्रभावी होकर कैंसर की कारक कोशिकाओं के विस्तार में मदद करते हैं। कई बार कैंसर के उपचार के दौरान लगातार वजन गिरने और उपचार प्रभावी नहीं होने के पीछे भी यही कारण मुख्य होता है। यही कारण है जिसके चलते उपचार पर होने वाले खर्च में भी कई गुना बढ़ोतरी हो जाती है। वैसे भी इस बीमारी का उपचार खासा खर्चीला होता है। ऐसे में मात्र कुपोषण को अनदेखा किया जाना एक तरह से परेशानी को बढ़ाना ही है।

ध्यान रखा जाना चाहिए कि कुपोषण का प्रबंधन करने से मरीज का वजन कम होने संबंधी की जटिलताओं में कमी हो जाती है, और मरीज उनके अनावश्यक दुष्प्रभावों से बच जाता है। इसके अलावा कैंसर के निदान में सर्जरी के विकल्प को भी दूर करता है। यह जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए कैंसर के उपचार के दौरान, उससे पहले या बाद में अतिरिक्त पोषण लेना बीमारी से बाहर आने में मदद करता है। हालांकि इलाज के दौरान विभिन्न तरह के भोजन में परहेज की अवस्था में स्वाद के विकल्पों में कमी के कारण अतिरिक्त पोषण लेना कई बार मुश्किल होता है। इसके बावजूद भी हाई प्रोटीन डायट के जरिए और थोड़ी-थोड़ी देर पर आहार लेकर इस कमी से पार पाया जा सकता है। सौंफ और अदरक के साथ प्रचुर मात्रा में पानी लेना भी वमन से पैदा हुई समस्याओं तथा अतिरिक्त पोषण के रूप में एक विकल्प की तरह मौजूद है। इसमें खट्टे और मसालेदार खानों से परहेज करना चाहिए परंतु मिल्कशेक और खीर आदि दूध से बने पदार्थ पोषण के विभिन्न अवयवों की पूतत में सहायक होते हैं। प्रचुर मात्रा में पानी और रेशेदार भोजन भी कैंसर के कारण पैदा हुए कब्ज से लड़ने में सहायक होता है। आलू और केला भी कैंसर की अवस्था में अच्छे पोषक पदार्थ हैं। कहना न होगा कि स्वस्थ भोजन पर ध्यान देने से कैंसर के निदान में काफी हद तक मदद मिलती है। इसके अलावा, शरीर में शक्ति भी संरक्षित होती है। गौरतलब है कि कैंसर के उपचार के दौरान शरीर को कई तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। मरीज को और उसके तीमारदारों को इस बाबत परामर्श देना जरूरी होता है। चूंकि पोषण विशेषज्ञ इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं और उनका यह दायित्व भी होता है। इसलिए कैंसर के चिकित्सकों को अपने साथ हमेशा पोषण विशेषज्ञों की टीम रखनी चाहिए। इन पोषण विशेषज्ञों को रोगी के परिजनों को भी समय-समय पर पोषण-स्तर बढ़ाने के लिए आसान सुझाव देने चाहिए। उन्हें रोगियों को पोषण और भोजन के माध्यम से देखभाल पर ध्यान देना चाहिए। कैंसर के लक्षणों में कमी के लिए या कमी के साथ भोजन के अवयवों में भी बदलाव करने चाहिए। ये बदलाव रोगी के खाने के तरीके या अंतराल के आधार पर भी होने चाहिए। पोषण की दृष्टि से हस्तक्षेप की कैंसर के निदान में बड़ी भूमिका है। यह रोगी में जटिलताओं को घटाने के साथ ही सरवाइवल रेट को भी बढ़ाता है।

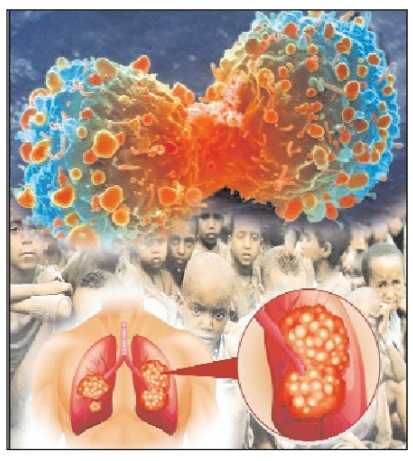

यह भी गौर करने वाली बात है कि खाने की अच्छी आदतें भी कैंसर से दूर रहने या कैंसर के निदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पोषण में सुधार से कैंसर के दूसरे कारक तत्वों में भी सुधार के लक्षण कई जगह देखे गए हैं। इसलिए कैंसर के इलाज में पोषण की अनिवार्य भूमिका मानकर पहल करने से काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। वयस्क अवस्था को प्राप्त होते ही शरीर के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ की सलाह एक बार जरूर लेनी चाहिए। कई बार हमारे रोजमर्रा के जीवन में मौजूद वस्तुओं और आस-पड़ोस में उपलब्ध वनस्पतियों में अलग-अलग मात्रा के मिश्रण से जरूरी पोषक पदार्थ की उपलब्धता हो सकती है। यह हमारे शरीर को कैंसर से दूर रखने में भी मददगार हो सकता है। कैंसर का लक्षण शरीर में पैदा होने पर तो निश्चित रूप से सही पोषण शरीर को देना चाहिए। (लेखिका मुख्य नैदानिक पोषण विज्ञानी, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली)

रुपये में तीन सत्रों से जारी गिरावट थमी, 10 पैसे बढ़कर 73.50 रुपये प्रति डॉलर पर हुआ बंद

मुंबई, रुपये में पिछले तीन कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। घरेलू शेयर बाजारों में सुधार होने के बीच बृहस्पतिवार को विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 10 पैसे की तेजी के साथ 73.50 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में कारोबार की शुरुआत में रुपया कमजोरी का रुख लिए 73.77 रुपये प्रति डॉलर पर खुला और कारोबार के दौरान 73.48 के दिन के उच्चतम स्तर और 73.85 के निम्नतम स्तर को छूने के बाद यह अपने पिछले बंद भाव के मुकाबले 10 पैसे ऊंचा रहकर 73.50 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 73.60 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी मुद्रा का रुख दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.11 प्रतिशत घटकर 92.54 रह गया। वहीं, ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.29 प्रतिशत बढ़कर 72.81 डालर प्रति बैरल पर पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित संवेदनशील सूचकांक 54.81 अंक की तेजी दर्शाता 58,305.07 अंक पर बंद हुआ। एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशक, पूंजी बाजार में शुद्ध बिकवाल रहे और उन्होंने बुधवार को 802.51 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की।

सोनी ने भारत में 28,990 रुपये में नया साउंडबार किया पेश

नई दिल्ली। सोनी इंडिया ने गुरुवार को अपना 5.1 चैनल होम सिनेमा सिस्टम-एचटी-एस 40आर को लॉन्च किया। 28,990 रुपये की कीमत में, नया होम थिएटर सिस्टम डॉल्बी डिजिटल टेक्नोलॉजी और वायरलेस सब और रियर स्पीकर के साथ आता है जो इमर्सिव सिनेमैटिक सराउंड साउंड उत्पन्न करता हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, नए एचटी-एस 40आर 5.1 एच साउंडबार के साथ, आप अपना होम थिएटर सिस्टम सेट कर सकते हैं। एक वायरलेस एम्पलीफायर के साथ जो रियर स्पीकर को पावर देता है, आपके रास्ते में आने के लिए आगे और पीछे के बीच कोई तार नहीं हैं। साउंडबार एक सबवूफर और दो असतत वायरलेस रियर स्पीकर के साथ आता है। तीन चैनल बार स्पीकर, रियर स्पीकर और एक सबवूफर की विशेषता वाला साउंडबार वास्तविक 5.1 एच सराउंड साउंड सिस्टम प्रदान करने के लिए एक साथ काम करता है। यह 4 ध्वनि मोड के साथ आता है। इसके अलव, नाइट और वॉयस मोड भी हैं। यूजर्स के देखने और सुनने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सबवूफर के वॉल्यूम नियंत्रण का भी उपयोग कर सकते हैं। साउंडबार सभी सोनी सेंटर, ई-कॉमर्स पोर्टल और भारत के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर उपलब्ध है।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को उच्चतम न्यायालय से मिली बड़ी राहत, डीएमआरसी को ब्याज सहित चुकाने होंगे 2800 करोड़ रुपए

नेशनल डेस्क।

उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति किये जाने के पंचाट के फैसले को गुरुवार को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति एन नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 2800 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के आदेश के खिलाफ दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) की अपील ठुकरा दी। न्यायालय ने डीएमआरसी को कहा है कि वह रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये के साथ-साथ ब्याज का भी भुगतान करे। यह मामला 2008 में रिलायंस इंफ्रा और डीएमआरसी के बीच दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस को लेकर हुए समझौते से जुड़ा है। रिलायंस इंफ्रा ने 2012 में यह समझौता रद्द कर दिया था। पंचाट के फैसले के तहत डीएमआरसी को क्षतिपूर्ति के तौर रिलायंस इंफ्रा को 2800 करोड़ रुपये देने थे। रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की ताजा वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार डीएएमईपीएल के पक्ष में यह फैसला ब्याज सहित 63.2 करोड़ डॉलर या 4,600 करोड़ रुपये से अधिक का है। मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने मई, 2017 में अपने फैसले में एयरपोर्ट मेट्रो की परिचालक के इस दावे को स्वीकार कर लिया था कि संरचनात्मक खामियों की वजह से इस लाइन पर परिचालन व्यावहारिक नहीं है। कंपनी के अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि डीएएमईपीएल इस राशि का इस्तेमाल अपने ऋणदाताओं को बकाया के

भुगतान के लिए करेगी। डीएएमईपीएल ने 2008 में एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का परिचालन 2038 तक करने के लिए डीएमआरसी से करार किया था। दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद डीएएमईपीएल ने एयरपोर्ट मेट्रो लाइन का परिचालन रोक दिया था।

एमएफ को अगस्त में मिला 8,666 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली।

शेयर बाजारों में तेजी के बीच नई कोष पेशकशों (एनएफओ) में मजबूत प्रवाह तथा एसआईपी में स्थिरता के बीच इक्विटी म्यूचुअल फंड (एमएफ) में अगस्त में 8,666 करोड़ रुपए का निवेश आया। यह लगातार छठा महीना है कि जबकि इक्विटी एमएफ में निवेश का प्रवाह सकारात्मक रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों के अनुसार इससे पहले जुलाई में इन कोषों में 22,583 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया था। इक्विटी योजनाओं में जून में 5,988 करोड़ रुपए, मई में 10,083 करोड़ रुपए, अप्रैल में 3,437 करोड़ रुपए और मार्च में 9,115 करोड़ रुपए का निवेश आया था। इससे पहले जुलाई, 2020 से फरवरी, 2021 तक इक्विटी योजनाओं से लगातार निकासी हुई थी। इस निवेश से अगस्त के अंत तक म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां (एयूएम) बढ़कर 36.6 लाख करोड़ रुपए के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गईं। जुलाई अंत तक यह 35.32 लाख करोड़ रुपए थीं।

गूगल ने भारत में डिजिटल समाचार स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किया

नयी दिल्ली, गूगल ने बृहस्पतिवार को देश में स्वतंत्र स्थानीय या एकल विषय पर केंद्रित पत्रकारिता संगठनों के लिए एक प्रोत्साहन कार्यक्रम 'जीएनआई स्टार्टअप लैब इंडिया' की घोषणा की।गूगल न्यूज अपनी जीएनआई पहल के तहत चार महीने का कार्यक्रम शुरू करेगी, जो स्वतंत्र स्थानीय या एकल विषय पर केंद्रित पत्रकारिता संगठनों को गहन शिक्षण, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं के जरिए वित्तीय तथा परिचालन स्थिरता हासिल करने में मदद करेगा। गूगल ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इकोस (एक वैश्विक नवाचार प्रयोगशाला) और डिजीपब न्यूज इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी में बनाया गया जीएनआई स्टार्टअप लैब इंडिया कार्यक्रम स्थानीय और वंचित समुदायों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पत्रकारिता की मदद करेगा। ब्लॉग पोस्ट के मुताबिक सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार संगठन स्टार्टअप कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 18 अक्टूबर 2021 तक किया जा सकता है और भारत में पहले समूह के रूप में 10 स्वतंत्र डिजिटल समाचार प्रकाशकों का चयन किया जाएगा।

आरबीआई के पीसीए प्रतिबंध हटाने से, यूको बैंक के शेयरों में 10 फीसदी की वृद्धि

मुंबई।

यूको बैंक के शेयरों में 10 फीसदी से अधिक की तेजी आई है, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसे तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) ढांचे से बाहर लाने और प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। दोपहर करीब 12.40 बजे, बीएसई पर इसके शेयर 14.17 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो इसके पिछले बंद से 10.62 प्रतिशत अधिक है। इससे पहले यह 14.85 रुपये प्रति शेयर के उच्च स्तर को छू गया था। आरबीआई ने कहा, यूको बैंक को पीसीए ढांचे से बाहर कर दिया है और प्रतिबंध हटा दिए हैं। हालांकि, इसने कहा कि निर्णय कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा यूको बैंक के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और यह नोट किया कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए इसके प्रकाशित परिणामों के अनुसार, बैंक पीसीए मापदंडों का उल्लंघन नहीं किया है। बैंक ने एक लिखित प्रतिबद्धता प्रदान की है कि वह न्यूनतम नियामक पूंजी के मानदंडों का पालन करेगा, निवल एनपीए और उत्तोलन अनुपात निरंतर आधार पर और इसने आरबीआई को संरचनात्मक और प्रणालीगत सुधारों से अवगत कराया है, जो बैंक को इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद करेगा। आरबीआई के बयान में कहा गया है, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि यूको बैंक को कुछ शर्तों और निरंतर निगरानी के अधीन पीसीए प्रतिबंधों से बाहर कर दिया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ढांचे के तहत अन्य दो बैंक हैं। रिजर्व बैंक ने पीसीए ढांचे के हिस्से के रूप में, पूंजी से जोखिम भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर), शुद्ध गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए), और परिसंपत्तियों पर रिटर्न (आरओए) सहित तीन मापदंडों के संदर्भ में कुछ नियामक ट्रिगर बिंदु निर्दिष्ट किया हैं। पीसीए ढांचा केवल वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है।

माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स कंट्रोलर फर्मवेयर अपडेट को किया रोलआउट

सैन फ्रांसिस्को।

माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लूटूथ सपोर्ट, एक्सबॉक्स एलीट वायरलेस कंट्रोलर सीरीज 2 और एक्सबॉक्स एडेप्टिव कंट्रोलर्स के साथ एक्सबॉक्स वन कंट्रोलर्स के लिए नए फर्मवेयर अपडेट की टेस्टिंग शुरू कर दी है। नया अपडेट अगली पीढ़ी की सुविधाएँ प्रदान करता है, जो पहले केवल एक्सबॉक्स सीरिज एक्सएस एक्स वन एस कंट्रोलर्स पर उपलब्ध था, जिसमें बेहतर क्रॉस-डिवाइस कनेक्टिविटी और कम लेटेंसी शामिल है। एक्सबॉक्स एक्सेसरीज के प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर डेनियल रुइज ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, हमारा मानना है कि लोगों के पास पहले से मौजूद एक्स बॉक्स एक्सेसरीज के साथ बैकवर्ड कम्पैटिबिलिटी बनाए रखना महत्वपूर्ण है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम सबसे अच्छा गेमिंग अनुभव प्रदान करें, चाहे आप किसी भी तरह से खेलना चाहें। ये कंट्रोलर ब्लूटूथ कम ऊर्जा का समर्थन हैं, जो सभी उपकरणों में बेहतर अनुकूलता प्रदान करता है और बेहतर अनुभव की अनुमति देता है। यूजर्स चलते-फिरते एक्सबॉक्स गेम पास अल्टीमेट के साथ कंसोल या क्लाउड गेमिंग से रिमोट प्ले के लिए विंडोज 10 पीसी, आईओएस 15 और इसके बाद के संस्करण और ब्लूटूथ लो एनर्जी वाले एंड्रॉइड डिवाइस पर वायरलेस तरीके से खेल सकेंगे। फर्मवेयर अपडेट स्थापित करने के बाद, ये नियंत्रक एक ब्लूटूथ होस्ट (जैसे, स्मार्टफोन) और एक एक्सबॉक्स वायरलेस होस्ट (जैसे, एक्सबॉक्स कंसोल) को याद रखेंगे, ताकि यूजर्स जोड़ी बटन के एक साधारण डबल टैप के साथ पहले से जुड़े उपकरणों के बीच जल्दी और निर्बाध रूप से स्विच कर सकें। इस फर्मवेयर अपडेट के साथ, माइक्रोसॉफ्ट इन कंट्रोलर के लिए डायनामिक लेटेंसी इनपुट (डीएलआई) का इनोवेशन ला रहा है, जो डायनेमिक लेटेंसी इनपुट आपके एक्सबॉक्स सीरिज एक्स में कंट्रोलर इनपुट को अधिक कुशलता से डिलीवर करता है। एक अधिक प्रतिक्रियाशील गेमिंग अनुभव के साथ है। कंपनी ने कहा, हम ब्लूटूथ सपोर्ट, एक्स बॉक्स एलीट वायरलेस कंट्रोलर सीरीज 2 और एक्सबॉक्स एडेप्टिव कंट्रोलर के साथ एक्सबॉक्स वन कंट्रोलर्स के लिए नई सॉफ्टवेयर सुविधाओं को लाने के लिए उत्साहित हैं, जो पहले केवल अगली जनरेशन के एक्सबॉक्स सीरीज एक्स वन एस कंट्रोलर पर उपलब्ध है। फर्मवेयर अपडेट आज अल्फा स्किप-अहेड और अल्फा यूजर्स के लिए उपलब्ध है, और आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त फ्लाइट रिंग के लिए उपलब्ध होगा।

मारुति सुजुकी ने उन्नत टेलीमैटिक्स तकनीक 'सुजुकी कनेक्ट' पेश की

नई दिल्ली। आम आदमी की कार कहलाने वाली देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने गुरुवार को कहा कि उसने एरेना रिटेल चैनल के जरिए बड़े पैमाने पर बेचे जाने वाले वाहनों के लिए अपनी उन्नत टेलीमैटिक्स तकनीक 'सुजुकी कनेक्ट' की पेशकश की है। कंपनी ने 2018 में नेक्सा आउटलेट्स के माध्यम से बेचे जाने वाले अपने प्रीमियम वाहनों में इस तकनीक को पेश किया था। सुजुकी कनेक्ट एक उन्नत टेलीमैटिक्स समाधान है, जो सुरक्षा अलर्ट, जियो-फेंस, वाहन स्थिति जैसी सुविधाओं से लैस है और इंटरनेट तथा वायरलेस कनेक्टिविटी का इस्तेमाल करता है। एमएसआईएल के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि नेक्सा में पेशकश के बाद से सुजुकी कनेक्ट को 50,000 से अधिक ग्राहकों ने अपनाया है।

पहली तिमाही में 'वी' आकार के सुधार से मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद की पुष्टि हुई: वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली,

वित्त मंत्रालय के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी की भीषण दूसरी लहर के बाजवूद वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 'वी' आकार के सुधार से भारत की मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियाद का पता चलता है। वित्त मंत्रालय ने अपनी ताजा मासिक आर्थिक समीक्षा में केरल और महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में तेजी पर भी चिंता जताई और इन दोनों राज्यों में महामारी नियंत्रण तथा प्रबंधन को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के

20.1 प्रतिशत की दर से बढ़ने से ''भीषण दूसरी लहर के बावजूद भारत की लचीली वी-आकार की भरपाई'' का पता चलता है। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में 24.4 प्रतिशत की गिरावट आई थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि इस साल अब तक मानसून नौ प्रतिशत कम है, इसके बावजूद तीन सितंबर तक खरीफ की बुवाई सामान्य स्तर के मुकाबले 101 प्रतिशत हो चुकी थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि धान की रिकॉर्ड खरीद और ट्रैक्टर की बिक्री में बढ़ोतरी से आने वाले महीनों में मजबूत ग्रामीण मांग के लिए अच्छी संकेत मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, ''बिजली की खपत, रेल भाड़ा, राजमार्ग टोल संग्रह, ई-वे बिल, डिजिटल लेनदेन, हवाई यातायात और मजबूत जीएसटी संग्रह से सुधार स्पष्ट है। विनिर्माण और सेवाओं, दोनों क्षेत्रों में भारत का पीएमआई आर्थिक विस्तार की शुरुआत का संकेत देता है।''कोविड-19 महामारी को लेकर रिपोर्ट में कहा गया कि केरल अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। देश में रोजाना आने वाले नए मामलों में केरल का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत है। किसी दूसरे राज्य के मुकाबले केरल में अधिक लोगों की जान संक्रमण से जा रही है। इसी तरह महाराष्ट्र को लेकर भी सावधानी बरतने की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने आने वाले त्योहारी महीनों में संभावित तीसरी लहर के प्रति आगाह किया है।

कोटक महिंद्रा बैंक ने 2 महीने के लिए होम लोन की ब्याज दर घटाकर 6.5 प्रतिशत की

मुंबई।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने गुरुवार को अपने होम लोन की ब्याज दरों को 15 आधार अंकों (बीपीएस) से घटाकर 6.50 फीसदी करने की घोषणा की है। 6.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की यह विशेष दर 10 सितंबर से 8 नवंबर, 2021 की अवधि के लिए सीमित अवधि के त्यौहारी सीजन की पेशकश है।

घटी हुई दर सभी ऋण राशियों पर उपलब्ध होगी और यह उधारकर्ता की क्रेडिट प्रोफाइल से जुड़ी होगी। संशोधित दर नए होम लोन और बैलेंस ट्रांसफर लोन दोनों पर लागू होगी। कोटक महिंद्रा बैंक के उपभोक्ता संपत्ति के अध्यक्ष अंबुज चंदना ने कहा, लोग आरामदायक आवास की तलाश में हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ काम कर सकता है, मनोरंजन कर सकता है और गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकता है। कोटक की अविश्वसनीय 6.50 प्रतिशत गृह ऋण ब्याज दर अब किसी के सपनों का घर भी बनाती है अधिक किफायती बनाता है। बैंक ने कहा कि कोटक डिजी होम लोन के साथ, होम लोन आवेदक अब अपनी ऋण राशि पात्रता, ऋण की अवधि, ब्याज दर और ईएमआई के साथ तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी पत्र के लिए पूरी तरह से डिजिटल, पेपरलेस और कॉन्टैक्टलेस प्रक्रिया आवेदन कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं।

एडिडास इंडिया ने डिजिटल फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया

नई दिल्ली।

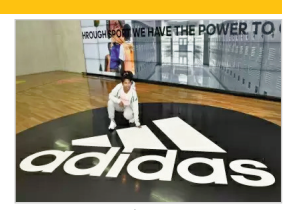

स्पोर्ट्सवियर की दिग्गज कंपनी एडिडास ने गुरुवार को देशभर के उपभोक्ताओं के लिए अपना डिजिटल फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च किया। उपभोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों और समीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सभी नई वेबसाइट की अवधारणा और क्यूरेट की गई थी। डिजिटल फ्लैगशिप स्टोर का फोकस एक सहज अनुभव, नवाचार, अत्याधुनिक यूआई और एक तेज इंटरफेस प्रदान करना है, जिससे उपभोक्ताओं को एक वैश्विक ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव मिलता है, जो डिजिटल रूप से बेहतर और निर्बाध है। वेबसाइट एक अभिनव तकनीक-संचालित अनुभव प्रदान करती है जो उपभोक्ताओं को डिजिटल स्टोर पर सहजता से नेविगेट करने और अपने पसंदीदा उत्पादों को आसानी से खरीदने में सक्षम बनाती है। पूरे डिजिटल फ्लैगशिप स्टोर में खोज से लेकर नेविगेशन तक उपभोक्ता एक सहायक अनुभव से गुजरते हैं जो उन्हें सही उत्पाद खोजने और खरीदने में सक्षम बनाता है। समर्थन मिलने और सर्वोत्तम क्रॉस-श्रेणी संवर्धन से उनकी समग्र ऑनलाइन खुदरा बिक्री में वृद्धि होती है। इसके अलावा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में काम चल रहा है, जो हर खेल के लिए गो-टू डेस्टिनेशन के रूप में काम करता है। फ्लैगशिप स्टोर रेंज रनिंग, लाइफस्टाइल, ट्रेनिंग और फुटबॉल जैसी रणनीतिक श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही महिलाओं और बच्चों के प्रमुख उपभोक्ता सेटों के प्रति अनुभव भी बढ़ाता है। भारत के ब्रांड एडिडास के वरिष्ठ निदेशक सुनील गुप्ता ने डिजिटल फ्लैगशिप स्टोर लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए कहा, हमारे नए डिजिटल स्टोर के लॉन्च के साथ हम उपभोक्ता प्रतिक्रिया की स्वीकृति के माध्यम से भारत में ब्रांड की विश्वसनीयता को मजबूत करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य एक ईकॉमर्स साइट से एक डिजिटल ब्रांड स्टोर तक की मानसिकता बनान है, जिसके मूल में उपभोक्ता का जुनून है। डिजिटल स्टोर का उद्देश्य हमारी विश्वसनीयता को डायल करना, उपभोक्ता अनुभव को बढ़ाना और हमारे स्थिरता प्रयासों पर नैरेटिव को आगे बढ़ाना है। नई तकनीक और बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफेस उपभोक्ताओं को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा।

फ्यूचर ग्रुप को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन मामले में दिल्ली एचसी में सभी सुनवाई पर रोक लगाई

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अमेजन की उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई को लेकर रोक लगा दी, जिसमें सिंगापुर के आपात निर्यातक (ईए) के फैसले को लागू करने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय और अन्य सभी प्राधिकरणों - सीसीआई, एनसीएलटी और सेबी के समक्ष आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगाएं - चार सप्ताह तक कोई अंतिम आदेश पारित न करें। शीर्ष अदालत ने 4 सप्ताह के बाद मामले में सुनवाई निर्धारित की है। फ्यूचर ग्रुप के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी और अमेजन के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने यह आदेश पारित किया। 3 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) की नई अपील पर दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए एक तारीख देगा।

शीर्ष अदालत ने एफआरएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा था, मुझे फाइल देखने दो और मैं एक तारीख दूंगा। एफआरएल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की थी।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

Sports

भारतीय टीम का एक और कोचिंग स्टाफ कोरोना के चपेट में

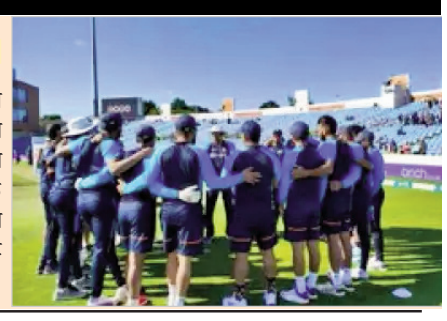

मैनचेस्टर। भारत और इंग्लैंड के बीच मेंचेस्टर में खेला जाने वाला पांचवा और अंतिम टेस्ट पर खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को भारतीय टीम का एक और कोचिंग स्टाफ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है। इएसपीएन क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय टीम के एक और कोचिंग स्टाफ कोविड-19 से पॉजिटिव पाया गया है जिसके चलते टेस्ट मैच के एक दिन पहले होने वाले अभ्यास सत्र को स्थगित कर दिया गया। भारतीय टीम के मुख्य कोच और कोचिंग स्टाफ पहले ही कोरोना के चपेट में आ गए थे, जिसके चलते वह अभी लंदन में क्वारंटीन में हैं और टीम के साथ मैनचेस्टर नहीं गए। रिपोर्ट में यह माना गया है कि खिलाड़ियो और कोचिंग स्टाफ का बुधवार को टेस्ट किया गया जिसमें एक स्टाफ पॉजिटिव पाया गया। गुरुवार को फिर से टीम के सभी खिलाड़ियों का टेस्ट कराया गया जिसका परिनाम का इंतजार किया जा रहा है। पूरी टीम को अगले आदेश तक होटल रुम में ही रहना है।

15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई

द.अफ्रीका ने की टी20 विश्वकप टीम की घोषणा

जोहान्सबर्ग ।

टी-20 क्रिकेट में अनकैप्ड खिलाड़ी केशव महाराज को दक्षिण अफ्रीका की टी-20 विश्व कप टीम में चुना गया है, जबकि अनुभवी एवं सीनियर खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस, क्रिस मॉरिस और इमरान ताहिर बाहर हो गए हैं। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका की ओर से गुरुवार को टी-20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है, जिसमें चयनकर्ताओं ने केशव महाराज सहित तीन स्पिनरों को चुना है। दुनिया के नंबर एक टी-20 गेंदबाज तबरेज शम्सी और ब्योर्न फोर्टुइन दो अन्य स्पिनर हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर जॉर्ज लिंडे के रूप में टीम में तीसरा स्पिनर भी हैं, जो रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल होंगे। टेम्बा बावुमा को फिर से टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जिनके टूर्नामेंट से पर्याप्त समय पहले अंगूठे की चोट से उबरने की उम्मीद है। बावुमा की गैर मौजूदगी में श्रीलंका के खिलाफ आगामी टी-20 सीरीज में केशव महाराज अपना टी-20 अंतरराष्ट्रीय पदार्पण करेंगे। उन्होंने अभी तक 36 टेस्ट और 14 वनडे मैच खेले हैं। 104 टी-20 मुकाबलों में उन्होंने 6.62 की इकॉनमी के साथ 83 विकेट लिए हैं। क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन जैसे इन फार्म बल्लेबाजों की मौजूदगी से दक्षिण अफ्रीका का बल्लेबाजी विभाग मजबूत लग रहा है। टीम में ऑल राउंडर वियान मल्डर भी शामिल हैं जो बल्लेबाजी लाइन अप को और मजबूती देंगे। इसके अलावा तेज गेंदबाजी के मोर्चे पर कैगिसो रबादा, लुंगी एनगिदी और एनरिक नॉर्त्जे उपलब्ध हैं।

दक्षिण अफ्रीकाई टीम :

टेम्बा बावुमा, क्विंटन डी कॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, हेनरिक क्लासेन, केशव महाराज, एडन मार्करम, डेविड मिलर, वियान मल्डर, लुंगी एनगिदी, एनरिक नॉर्त्जे, ड्वेन प्रिटोरियस, कैगिसो रबादा, तबरेज शम्सी, रासी वान डर डुसेन।

रिजर्व खिलाड़ी :

जॉर्ज लिंडे, एंडिले फेहलुकवेओ, लिजाद विलियम्स।

धोनी को मेंटोर बनाना उनके अनुभव के इस्तेमाल का एक तरीका है : गांगुली

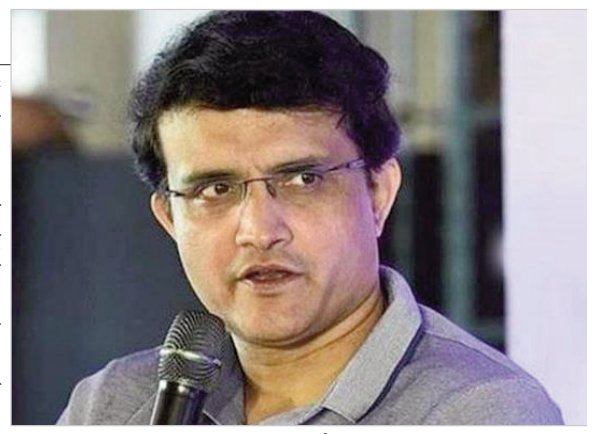

नयी दिल्ली,

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गुरूवार को कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को आगामी टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम का मार्गदर्शक (मेंटोर) उनके अपार अनुभव का फायदा उठाने के लिये बनाया गया है। बीसीसीआई ने बुधवार को यह घोषणा कर सभी को हैरान कर दिया कि धोनी 17 अक्टूबर से संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में होने वाले टी20 विश्व कप के लिये भारतीय टीम के मेंटोर होंगे। गांगुली ने बीसीसीआई के एक ट्वीट में कहा, ''धोनी को टीम में शामिल करना टी20 विश्व कप के लिये उनके अपार अनुभव का इस्तेमाल करने का तरीका है। मैं धोनी का शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिये टीम की मदद के लिये बीसीसीआई की पेशकश स्वीकार कर ली। '' भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में शुमार विकेटकीपर बल्लेबाज धोनी की अगुवाई में भारत ने दो विश्व कप खिताब - दक्षिण अफ्रीका में 2007 टी20 विश्व कप और भारत में 2011 वनडे विश्व कप - जीते हैं। धोनी इस समय अपनी इंडियन प्रीमियर लीग टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हैं और संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से बहाल होने वाली टी20 लीग की तैयारियों में जुटे हैं।

मुक्केबाजी में कमेंट्री करेंगे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप

वाशिंगटन : अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुक्केबाजी के एक नुमाइशी मुकाबले में कमेंट्री करेंगे जिसमें पूर्व हैवीवेट चैम्पियन इवांडर होलीफील्ड भी शामिल होंगे। ट्रंप के साथ उनके बेटे डोनाल्ड जूनियर भी होंगे। हॉलीवुड में होने वाले इस मुकाबले की फीड एफआईटीई डॉट टीवी पर उपलब्ध होगी। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे महान लड़ाके और मुकाबले पसंद है। इस बार मैं शनिवार की रात ऐसे ही एक मुकाबले का हिस्सा रहूंगा और अपने विचार भी रखूंगा। आप इसे चूकना नहीं चाहेंगे। पहले यह मुकाबला लॉस एंजिलिस में होना था जिसमें आस्कर डे ला होया को विटोर बेलफोर्ट का सामना करना था। डे ला होया के कोरोना संक्रमित होने के कारण ऐन मौके पर होलीफील्डको शामिल किया गया। होलीफील्ड की उम्र को देखते हुए कैलिफोर्निया राज्य एथलेटिक आयोग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया जिसकी वजह से अब मुकाबला फ्लोरिडा में हो रहा है। होलीफील्ड अगले महीने 59 वर्ष के हो जायेंगे और 2011 से रिंग में नहीं उतरे हैं।

US Open :

जोकोविच सेमीफाइनल में, इतिहास रचने के करीब

न्यूयार्क :

दुनिया के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच यहां बुधवार रात को पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मैच में इटली के मातियो बेरेटिनी को हराकर वर्ष के आखिरी ग्रैंड स्लेम यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। शीर्ष वरीयता प्राप्त जोकोविच ने बेरेटिनी को हराने से पहले धीमी शुरुआत की। पहला सेट 5-7 से हारने के बाद वापसी करते हुए उन्होंने बेरेटिनी को 6-2, 6-2, 6-3 से हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसी के साथ वह इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वह अब इस कैलेंडर-वर्ष में चार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने से सिर्फ दो जीत दूर हैं जो एक ऐसी उपलब्धि है जो पुरुष टेनिस में आधी सदी से अधिक समय बीत जाने तक किसी ने हासिल नहीं की है। उल्लेखनीय है कि ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी रॉड लेवर ने 1969 सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम खिताब जीते थे। 34 वर्षीय जोकोविच ने मैच जीतने के बाद कहा कि पहला सेट हारने के बाद मैंने इसको भुलाते हुए वापसी की। मैंने दूसरे सेट की शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया था। मैंने अपने टेनिस को एक अलग स्तर पर रखा। निश्चित रूप से यह टूर्नामेंट में अब तक खेले गए मेरे सर्वश्रेष्ठ तीन सेट हैं। यह एक बेहतरीन मैच था। कोर्ट और कोर्ट के बाहर बहुत ऊर्जा है। मातियो एक शानदार खिलाड़ी हैं और एक स्थापित टॉप 10 खिलाड़ी हैं। जब भी हम एक-दूसरे के सामने होते हैं तो यह हमेशा एक करीबी लड़ाई होती है। आज रात कुछ अलग नहीं था।

संक्षिप्त समाचार

अब हमारा टारगेट एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतना : लालरेमसियामी

नई दिल्ली : युवा स्ट्राइकर लालरेमसियामी का कहना है कि टोक्यो खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद अब समय अगले साल एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलिम्पिक के लिए क्वालीफाई करने पर ध्यान लगाने का है। मिजोरम की 21 साल की खिलाड़ी टीम के पहली बार ओलिम्पिक सैमीफाइनल तक के सफर के शानदार प्रदर्शन का अहम हिस्सा रही थीं। भारतीय महिला टीम टोक्यो ओलिम्पिक में दुनिया की कुछ शीर्ष टीमों के खिलाफ खेली। रानी रामपाल की अगुवाई वाली टीम ने 3 बार की ओलिम्पिक स्वर्ण पदक विजेता आस्ट्रेलिया को क्वार्टरफाइनल में 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया जिससे वह पहली बार ओलिम्पिक के सेमीफाइनल में पहुंची जिसमें उसे अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा। लालरेमसियामी ने कहा कि हमने क्वार्टरफाइनल में आस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया और ओलिम्पिक में पहली बार सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया। इतिहास का हिस्सा बनना बहुत विशेष अहसास है और मैं इसे जीवन भर याद रखूंगी। वर्ष 2019 में एफआईएच महिला सीरीज फाइनल्स के दौरान अपने पिता के निधन की खबर सुनने के बावजूद लालरेमसियामी ने टीम के साथ रूकने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने यह टूर्नामेंट जीत लिया था। टोक्यो में इतिहास रचने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा बनकर अपने दिवंगत पिता का सपना पूरा करने वाली लालरेमसियामी अब ओलंपिक पदक जीतने का लक्ष्य बनाए हैं।

कोविड के कारण सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट रद्द

नई दिल्ली।

विश्व बैडमिंटन महासंघ (बीडब्ल्यूएफ) ने गुरूवार को सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय सुपर 300 टूर्नामेंट रद्द कर दिया। लगातार दूसरे साल इस प्रतियोगिता को आयोजित नहीं करने का फैसला किया गया है। कोविड-19 महामारी के चलते पिछले साल भी इसे रद्द कर दिया गया था जिसे इस साल लखनऊ में 12 से 17 अक्टूबर तक खेला जाना था। खेल की शीर्ष संस्था ने एक बयान में कहा कि बीडब्ल्यूएफ टूर्नामेंट कैलेंडर 2021 के अपडेट की अगस्त में हुई घोषणा में आगे बीडब्ल्यूएफ पुष्टि कर सकता है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय 2021 टूर्नामेंट अब रद्द हो गया है। बीडब्ल्यूएफ को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई जटिलताओं और पाबंदियों के कारण कई टूर्नामेंट को रद्द करने पड़े थे। उसने भारत में इस टूर्नामेंट को रद्द करने के पीछे का कारण नहीं बताया। बयान के अनुसार- टूर्नामेंट के आयोजक भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) ने स्थानीय सरकारी अधिकारियों और बीडब्ल्यूएफ के साथ सलाह मशविरा कर यह फैसला किया है। इसके अनुसार बीडब्ल्यूएफ को टूर्नामेंट रद्द करने पर खेद है लेकिन वह पूरे साल बैडमिंटन टूर्नामेंट सीरीज के सुरक्षित आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले महीने भी बीडब्ल्यूएफ ने कोविड-19 महामारी के कारण टूर्नामेंट के आयोजन में पेचीदगियों के चलते कोरिया ओपन, मकाऊ ओपन और ताइपे ओपन रद्द कर दिये थे। चाइना ओपन, जापान ओपन, फुजोऊ चाइना ओपन और हांगकांग ओपन जैसे अन्य महत्वपूर्ण टूर्नामेंट भी वैश्विक स्वास्थ्य संकट के कारण रद्द कर दिये गये थे।

अश्विन का टी20 विश्व कप के लिए चयन भारतीय टीम को मजबूती देगा- गौतम गंभीर

मुंबई।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर ने कहा कि ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का टी20 विश्व कप के लिए टीम में चयन भारतीय टीम को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि अश्विन एक गुणवत्ता वाले क्रिकेटर हैं जिन्हें सफेद गेंद से अधिक क्रिकेट खेलना चाहिए था। अश्विन ने आखिरी बार जुलाई 2017 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था। गंभीर ने गुरुवार को स्टार स्पोर्ट्स पर फॉलो द ब्लूज शो में कहा, अश्विन के लिए बहुत खुश हूं। उन्हें वैसे भी सफेद गेंद के क्रिकेट से बाहर नहीं होना चाहिए था, अब वह वापस आ गए हैं। हमें चयनकताओं को श्रेय देना चाहिए उनके आने से टीम और मजबूत होगी। गंभीर ने कहा, अश्विन नई गेंद के साथ-साथ बीच के ओवरों में गेंदबाजी कर सकते हैं, उनसे आप डेथ में भी गेंदबाजी करा सकते हैं। मेरे लिए वह एक गुणवत्ता वाले क्रिकेटर है, जितना उन्होंने सफेद गेंद वाला क्रिकेट खेला है, उसकी तुलना में उन्हें और अधिक खेलना चाहिए था। 39 वर्षीय गंभीर ने सूर्यकुमार यादव के टी20 विश्व कप के टीम में जगह बनाने की प्रशंसा की और उन्होंने बताया कि सूर्या कैसे श्रेयस अय्यर से बेहतर हैं। गंभीर ने कहा, श्रेयस अय्यर की तुलना में सूर्यकुमार एक पूरी तरह से अलग वर्ग के खिलाड़ी हैं। टी20 क्रिकेट में आपको ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है जो अपरंपरागत हों, आप ऐसे लोगों को चाहते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में गेंद को हिट कर सके। उसके पास सभी शॉट हैं, खासकर नंबर चार पर, क्योंकि कभी-कभी नंबर चार सबसे काफी महत्वपूर्ण होता है। टी20 क्रिकेट में जब आप दो शुरूआती विकेट खो देते हैं तब चार नंबर का खिलाड़ी और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत अपने टी20 विश्व कप अभियान की शुरूआत 24 अक्टूबर को दुबई में ग्रुप 2 में अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा।

ईसीबी और बीसीसीआई के बीच मुलाकात, पांचवें टेस्ट को लेकर संशय

लंदन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) एक सहायक स्टाफ के कथित रूप से कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच को लेकर बैठक कर रहे हैं। बीसीसीआई के सूत्र ने आईएएनएस से कहा, ईसीबी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के बीच बैठक हो रही है। इससे पहले, भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और फील्डिंग कोच आर श्रीधर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। भारत पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है। भारत ने लॉर्ड्स टेस्ट और द ओवल में खेला गया चौथा टेस्ट मुकाबला जीता था जबकि इंग्लैंड ने हेडिंग्ले में खेला गया तीसरा मैच अपने नाम किया था।

पैरा-एथलीटों के असाधारण प्रदर्शन ने देश में खेल के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है: खेल मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेलमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 5 स्वर्ण और 8 रजत सहित कुल 19 पदक जीत कर इतिहास रचने वाले भारत के पैरा-एथलीटों को सम्मानित किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री निसिथ प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर खेल विभाग के सचिव रवि मित्तल, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती ऊषा शर्मा तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी पर उपस्थित थे। अनुराग ठाकुर ने सभी पैरा एथलीटों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी। ठाकुर ने कहा, ÷मुझे याद है 2016 के पैरालंपिक में, भारतीय दल के 19 पैरा-एथलीटों ने भाग लिया था, जबकि इस साल देश ने 19 पदक जीते हैं! आपने हमें दिखाया कि मानवीय भावना सबसे शक्तिशाली है! हमारी पदक तालिका में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है। पहली बार हमने टेबल टेनिस में पदक जीते हैं, तीरंदाजी में कई पदक जीते हैं, कैनोइंग और पावरलिफ्टिंग में पहली बार प्रतिस्पर्धा की है। हमने दो विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की तथा हमने और भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। भारत के पैरा-एथलीटों ने एक आदर्श पोडियम फिनिश दिया!

मैनचेस्टर टेस्ट : सीरीज जीतकर इतिहास रचने उतरेगा भारत

मैनचेस्टर।

भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ यहां ओल्ड ट्रेफोर्ड में शुक्रवार से होने वाले सीरीज के पांचवें और अखिरी टेस्ट मुकाबले को जीतकर इतिहास रचने उतरेगी। भारत के पास सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जीत इंग्लैंड में पहली बार ऐसा करने का मौका रहेगा। भारत ने ओल्ड ट्रेफोर्ड में नौ टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें से चार में उसे हार मिली है। पांच मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारत के पास यहां पहली बार टेस्ट जीतने का भी मौका रहेगा। भारत ने इससे पहले 1986 में इंग्लैंड में दो टेस्ट मैच जीते थे और वह 2-0 से सीरीज जीतने में कामयाब रहा था। यह तीसरी बार होगा जब भारत इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतेगा। इससे पहले उन्होंने 1971 में 1-0 और 1986 में 2-0 से जीत दर्ज की थी। भारत इस टेस्ट में कुछ परिवर्तन कर सकता है जिसमें जसप्रीत बुमराह को आराम देना रहेगा जिन्होंने लगातार चार टेस्ट मैच खेले हैं। इसके बाद उन्हें आईपीएल और टी20 विश्व कप में भी भाग लेना है। हालांकि, अंतिम टेस्ट की महत्वत्ता को देखते हुए उन्हें खेलाया जा सकता है। भारत अजिंक्य रहाणे को भी आराम दे सकता है और उनकी जगह मयंक अग्रवाल या सूर्यकुमार यादव को मौका मिल सकता है। एक बार फिर दारोमदार ओपनिंग जोड़ी पर रहेगा जिनसे मजबूत शुरूआत की जिम्मेदारी रहेगी। रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में पहले विकेट के लिए 83 रन जोड़े थे। इनकी शुरूआत के दम पर भारत ने दूसरी पारी में 466 रन बनाए थे और 367 रनों की बढ़त ली थी। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को खेलाता है या नहीं। इंग्लैंड की टीम में उपकप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर एकादश में वापसी करेंगे। इंग्लैंड शायद गेंदबाजी संयोजन में कुछ बदलाव कर सकता है।

इस मुकाबले के लिए दोनों टीमें इस प्रकार है :

इंग्लैंड : जोए रूट (कप्तान), मोइन अली, जेम्स एंडरसन, जोनाथन बेयरस्टो, रोरी बर्न्स, जोस बटलर, सैम करेन, हसीब हमीद, डैन लॉरेंस, जैक लीच, डेविड मालन, क्रेग ओवरटोन, ओली पोप, ओली रॉबिन्सन, क्रिस वोक्स और मार्क वुड।

भारत : लोकेश राहुल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली (कप्तान), अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), अभिमन्यु ईश्वरन, पृथ्वी शॉ, सूर्यकुमार यादव और प्रसिद्ध कृष्णा।

टी20 विश्व कप : अश्विन की लंबे समय बाद टी20 टीम में हुई वापसी

नई दिल्ली। भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भारतीय टेस्ट टीम के अहम सदस्य रहे हैं लेकिन हाल के वर्षों में उनका टी20 टीम में चयन नहीं हो रहा था। हालांकि, उन्हें अगले महीने यूएई और ओमान में होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में लिया गया है। भारत ने 17 अक्टूबर से होने वाले टी20 विश्व कप के लिए बुधवार रात 18 सदस्यीय भारतीय टीम घोषित की जिसमें तीन स्टैंडबाई खिलाड़ी शामिल हैं। अश्विन को भी इस टीम में जगह दी गई है। भारत टी20 विश्व कप में ग्रुप-2 में शामिल हैं जिसमें चिरप्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान भी है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद अश्विन को इंग्लैड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले चार मुकाबलों में एकादश में जगह नहीं दी गई। इस फैसले पर कई पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञों ने हैरानी जताई। लेकिन अश्विन का टी20 विश्व कप के लिए टीम में शामिल होना यह दर्शाता है कि चयनकर्ताओं ने युवा जोश के साथ-साथ अनुभव को भी महत्व दिया है। भारत ने टी20 विश्व कप 2007 में जीता था और इसके बाद से उसने अबतक इश टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीता है। अश्विन इसके चार साल बाद 2011 में हुए वनडे विश्व कप टीम का हिस्सा थे जिसने फाइनल में श्रीलंका को हराकर खिताब जीता था। अश्विन ने 12 जून 2010 को जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 में डेब्यू किया था और उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टी20 मैच नौ जुलाई 2017 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला। इसके बाद से अश्विन अबतक भारतीय टी20 टीम में शामिल नहीं रहे। हालांकि, चार साल के लंबे अंतराल के बाद उनकी टी20 टीम में वापसी हुई है। अश्विन ने भले ही पिछले चार साल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टी20 मुकाबला नहीं खेला हो लेकिन वह इस दौरान लगातार आईपीएल में खेलते आए हैं। अश्विन ने 159 आईपीएल मैचों में 27.68 के औसत से 139 विकेट लिए हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

गणेश चतुर्थी कल, नोट कर लें गणपति बप्पा की संपूर्ण पूजा विधि और स्थापना का शुभ मुहूर्त

देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार 10 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश की विधि-विधान से पूजा की जाती है। गणपति पूजन में बहुत से लोग 10 दिन के लिए घर में गणपति बप्पा का आयोजन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश को धूमधाम के साथ विदाई देकर विसर्जन करते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की कृपा से सुख-शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

गणपति स्थापना पूजन का शुभ मुहूर्त

गणेश चतुर्थी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 12 बजकर 17 मिनट पर अभिजीत मुहूर्त से शुरू होगा और रात 10 बजे तक पूजन का शुभ समय रहेगा। इस साल गणेश चतुर्थी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। गणेश चतुर्थी के दिन 11 बजकर 09 मिनट से 10 बजकर 59 मिनट तक पाताल निवासिनी भद्रा रहेगी। शास्त्रों के अनुसार, पाताल निवासिनी भद्रा का योग शुभ माना जाता है।

गणेश चतुर्थी पूजा विधि

गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान-ध्यान करके गणपति के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दोपहर के समय गणपति की मूर्ति या फिर उनका चित्र लाल कपड़े के ऊपर रखें। फिर गंगाजल छिड़कने के बाद भगवान गणेश का आह्वान करें। भगवान गणेश को पुष्प, सिंदूर, जनेऊ और दूर्वा (घास) चढ़ाए। इसके बाद गणपति को मोदक लड्डू चढ़ाएं, मंत्रोच्चार से उनका पूजन करें। गणेश जी की कथा पढ़ें या सुनें, गणेश चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें।

गणपति बप्पा को लगाएं भोग

गणेश जी को पूजन करते समय दूब, घास, गन्ना और बूंदी के लड्डू अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि गणपति जी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि तुलसी ने भगवान गणेश को लम्बोदर और गजमुख कहकर शादी का प्रस्ताव दिया था, इससे नाराज होकर गणपति ने उन्हें श्राप दे दिया था।

गणपति महोत्सव पर विशेष

भगवान गणेशजी का संपूर्ण परिचय

भगवान गणेशजी को भारतीय धर्म और संस्कृति में प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। उनकी पूजा के बगैर कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं होता। सभी मांगलिक कार्य में पहले गणेश जी की स्थापना और स्तुति की जाती है। आओ जानते हैं भगवान गणेशजी के संबंध में संपूर्ण परिचय।

माता पिता : भगवान शंकर और माता पार्वती।

गणेश जन्म : माता पार्वती द्वारा पुण्यक व्रत के फलस्वरूप गणेशजी का जन्म हुआ था। बाद के पुराणों में उनके जन्म के संबंध में कहा गया है माता ने अपनी सखी जया और विजया के कहने पर एक गण की उत्पति अपने मैल से की थी।

जन्म नाम : विनायक

अन्य नाम : सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकर्णक, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र, विघ्नराज, द्वैमातुर, गणाधिप, हेरम्ब, गजानन, अरुणवर्ण, गजमुख, लम्बोदर, अरण-वस्त्र, त्रिपुण्ड्र-तिलक, मूषकवाहन आदि।

गणेशजी के 12 प्रमुख नाम : सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्न-नाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन।

जन्म समय : भाद्रपद की चतुर्थी को मध्यान्ह के समय।

जन्म समय माथुर ब्राह्मणों के इतिहास अनुसार अनुमानत: 9938 विक्रम संवत पूर्व भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मध्याह्न के समय हुआ था। पौराणिक मत के अनुसार सतयुग में हुआ था।

स्थान : कैलाश मानसरोवार या उत्तरकाशी जिले का डोडीताल।

भाई : श्रीकार्तिकेय (बड़े भाई), सुकेश, जलंधर, अयप्पा और भूमा।

बहन : अशोक सुंदरी, ज्योतिष (ज्वाला देवी), मनसा देवी। शायद ये भी-जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतलि।

गणेशजी की पत्नियां : ऋद्धि और सिद्धि।

पुत्र : क्षेत्र (शुभ) और लाभ।

पौत्र : आमोद और प्रमोद।

ससुर : भगवान विश्वकर्मा

अधिपति : जल तत्व के अधिपति।

प्रिय पुष्प : लाल रंग के फूल।

प्रिय वस्तु : दुर्वा (दूब), शमी-पत्र।

प्रमुख अस्त्र : पाश और अंकुश।

गणेश वाहन : सिंह, मयूर और मूषक। सतयुग में सिंह, त्रेतायुग में मयूर, द्वापर युग में मूषक और कलियुग में घोड़ा है।

गणेशजी का जप मंत्र : ऊँ गं गणपतये नम: है।

अवतार : पुराणों में उनके 64 अवतारों का वर्णन है। सतयुग में कश्यप व अदिति के यहां महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेतायुग में उन्होंने उमा के गर्भ जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयुरेश्वर नाम से विख?यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहां पुन- जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेदव्यास के विनय करने पर सशर्त महाभारत लिखी।

गणेश जी का मस्तक : उन्हें गजानन इसलिए कहा गया कि उनके सिर को भगवान शंकर ने काट दिया था। बाद में उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा कर उन्हें पुन: जीवित किया गया। यह भी कहा जाता है कि शनिदेव जब बाल गणेश को देखने गए तो उनकी दृष्टि से उनका मस्तक भस्म हो गया था बाद में विष्णुजी ने एक हाथी का सिर उनके धड़ पर लगाकर उन्हें पुनर्जिवित कर दिया था।

अग्रपूजक कैसे बने : एक बार देवताओं में धरती की परिक्रमा की प्रतियोगिता हुई जिसमें जो सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाता उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई परंतु गणेश जी का वाहन तो मूषक था तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता शिव एवं पार्वती की ही परिक्रमा कर ली। ऐसा करके उन्होंने संपूर्ण ब्रह्माण्ड की ही परिक्रमा कर ली। तब सभी देवों की सर्वसम्मति और ब्रह्माजी की अनुशंसा से उन्हें अग्रपूजक माना गया। इसके पीछे और भी कथाएं हैं। पंच देवोपासना में भगवान गणपति मुख्य हैं।

गणेशजी की पसंद : उनका प्रिय भोग मोदक लड्डू, प्रिय पुष्प लाल रंग के फूल, प्रिय वस्तु दुर्वा (दूब), प्रिय वृक्ष शमी-पत्र, केल, केला आदि हैं। केसरिया चंदन, अक्षत, दूर्वा अर्पित कर कपूर जलाकर उनकी पूजा और आरती की जाती है। उनको मोदक का लड्डू अर्पित किया जाता है। उन्हें रक्तवर्ण के पुष्प विशेष प्रिय हैं।

गणेशजी का स्वरूप : जल तत्व के अधिपति, बुधवार और चतुर्थी के स्वामी और केतु एवं बुध के ग्रहाधिपति गणेश जी के प्रभु अस्त्र पाश और अंकुश है। वे मूषक वाहन पर सवार रहते हैं। वे एकदन्त और चतुर्बाहु हैं। अपने चारों हाथों में वे क्रमश- पाश, अंकुश, मोदक पात्र तथा वरमुद्रा धारण करते हैं। वे रक्तवर्ण, लम्बोदर, शूर्पकर्ण तथा पीतवस्त्रधारी हैं। वे रक्त चंदन धारण करते हैं।

भगवान गणेशजी का सतयुग में वाहन सिंह है और उनकी भुजाएं 10 हैं तथा नाम विनायक। श्री गणेशजी का त्रेतायुग में वाहन मयूर है इसीलिए उनको मयूरेश्वर कहा गया है। उनकी भुजाएं 6 हैं और रंग श्वेत। द्वापरयुग में उनका वाहन मूषक है और उनकी भुजाएं 4 हैं। इस युग में वे गजानन नाम से प्रसिद्ध हैं और उनका वर्ण लाल है। कलियुग में उनका वाहन घोड़ा है और वर्ण धूम्रवर्ण है। इनकी 2 भुजाएं हैं और इस युग में उनका नाम धूम्रकेतु है।

गणेशजी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंग : मस्तक प्रसंग, पृथ?वी प्रदक्षिणा प्रसंग, मूषक (गजमुख) वाहन प्राप्ति प्रसंग, गणेश विवाह प्रसंग, संतोषी माता उत्पत्ति प्रसंग, विष्णु विवाह में उन्हें नहीं बुलाने का प्रसंग, असुर (देवतान्तक, सिंधु दैत्य, सिंदुरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर) वध प्रसंग, महाभारत लेखन प्रसंग आदि। उन्होंने अपने भाई कार्तिकेय के साथ कई युद्धों में लड़ाई की थी।

गणेश ग्रंथ : गणेश का गाणपतेय संप्रदाय है। उनके ग्रंथों में गणेश पुराण, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, श्रीगणेश सहस्रनामावली, गणेशजी की आरती, संकटनाशन गणेश स्तोत्र, गणपति अथर्वशीर्ष, गणेशकवच, संतान गणपति स्तोत्र, ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र, मयूरेश स्तोत्र आदि।

एकदंत कैसे कहलाए गणेशजी

महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें एक लाख से ज्यादा श्लोक हैं। महर्षि वेद व्यास के मुताबिक यह केवल राजा-रानियों की कहानी नहीं बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा है। इस ग्रंथ को लिखने के पीछे भी रोचक कथा है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने स्वप्न में महर्षि व्यास को महाभारत लिखने की प्रेरणा दी थी।

महर्षि व्यास ने यह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें कोई इसे लिखने वाला न मिला। वे ऐसे किसी व्यक्ति की खोज में लग गए जो इसे लिख सके। महाभारत के प्रथम अध्याय में उल्लेख है कि वेद व्यास ने श्री गणेश जी को इसे लिखने का प्रस्ताव दिया तो वे तैयार हो गए। उन्होंने लिखने के पहले शर्त रखी कि महर्षि कथा लिखवाते समय एक पल के लिए भी नहीं रुकेंगे।

इस शर्त को मानते हुए महर्षि ने भी एक शर्त रख दी कि गणेश भी एक-एक वाक्य को बिना समझे नहीं लिखेंगे। इस तरह गणेश जी के समझने के दौरान महर्षि को सोचने का अवसर मिल गया।

महाभारत लिखने के दौरान जल्दबाजी के कारण ही श्री गणेश ने अपना एक दांत तुड़वा लिया था। दरअसल बिना रुके लिखने की शीघ्रता में यह दांत टूटा था। तभी से वे एकदंत कहलाए। लेकिन इतनी शीघ्रता के बाद भी श्री गणेश ने एक-एक शब्द समझ कर लिखा।

सबक- महाभारत लिखने वाले श्री गणेश आजकल के प्रबंधकों के लिए एक संदेश देते हैं। प्रबंधक चाहे एक श्रोता या एक वक्ता उसे हमेशा ही विषय को लेकर गंभीर रहना चाहिए। अच्छा लेखन या बेहतर संवाद तभी हो सकता है जब हमारी समझ और ज्ञान साफ हो।

श्रीगणेश चतुर्थी 2021 : राशि अनुसार यह मंत्र है शुभ आपके लिए...

श्रीगणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के मुहूर्त में की जाती है क्योंकि श्रीगणेश का जन्म दोपहर में हुआ था। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की निर्विघ्न जीवन प्रदान करते हैं। आइए हम सब भगवान गजानन की आराधना कर सुखी, सुरक्षित और समृद्ध जीवन की कामना करें। जानें राशिनुसार कौन-सा मंत्र जपना शुभ है आपके लिए-

राशिनुसार श्री गणेश जी की आराधना-

मेष- ऊँ अवनीश नम:।
वृषभ- ऊँ गजवक्र नम:।
मिथुन- ऊँ कीर्ति नम:।
कर्क- ऊँ दुर्जा नम:।
सिहं- ऊँ नमस्थेतू नम:।
कन्या- ऊँ अवनीश नम:।
तुला- ऊँ गजकर्ण नम:।
वृश्चिक- ऊँ विकट नम:।
धनु- ऊँ यशस्कर नम:।
मकर- ऊँ यंजकाय नम:।
कुंभ- ऊँ विश्वराजा नम:।
मीन- ऊँ शशि-वर्णम नम:।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

तालिबान की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री और मंत्री 11 सितंबर को ले सकते हैं शपथ

काबुल (एजेंसी)।

इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान (आईईए) की अंतरिम सरकार 11 सितंबर को पद की शपथ ले सकती है, जिस दिन 2001 में अमेरिका में 9/11 के हमलों की 20वीं बरसी भी है। रिपोटरें के अनुसार, नवगठित तालिबान सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए चीन, तुर्की, पाकिस्तान, ईरान, कतर, भारत और दिलचस्प रूप से अमेरिका सहित विभिन्न देशों को निमंत्रण दिया है। तालिबान ने अपने अंतरिम सरकारी अधिकारियों के नामों की घोषणा की है और इस बात पर जोर दिया है कि अफगानिस्तान में गठन एक कार्यवाहक व्यवस्था के तहत होगा। तालिबान अंतरराष्ट्रीय मान्यता की मांग कर रहा है और उसने देशों से युद्धग्रस्त राष्ट्र में अपने दूतावास फिर से खोलने का आह्वान किया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा, हम मानते हैं कि निवेश के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। हम चीन सहित सभी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। उन्होंने कहा, युद्ध समाप्त हो गया है, देश संकट से बाहर निकल रहा है। यह अब शांति और पुनर्निर्माण का समय है। हमें लोगों का समर्थन करने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान को मान्यता प्राप्त होने का अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को काबुल में अपने दूतावास खोलने चाहिए। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी तालिबान की घोषित अंतरिम सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है और उसने विभिन्न अन्य जातीय समूहों की गैर-समावेशीता पर सवाल उठाए हैं। यह नए सेटअप में तालिबान के विभिन्न पुराने नेताओं के प्रतिनिधित्व से भी खुश नहीं है, जो अंतराष्ट्रीय स्तर पर वांछित हैं और उनके सिर पर इनाम भी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक प्लेटफार्मों द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध हैं। अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों के अधीन हैं। कार्यवाहक आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी एफबीआई की मोस्ट वांटेड सूची में है, जिसके सिर पर एक करोड़ डॉलर का इनाम है। शरणार्थियों के लिए कार्यवाहक मंत्री के रूप में नियुक्त खलील हक्कानी के सिर पर 50 लाख डॉलर का इनाम है। सूची में वरिष्ठ पदों पर कई अन्य हैं जो या तो अमेरिका द्वारा नामित आतंकवादी समूहों के सदस्य हैं या अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में हैं, या ग्वांतानामो के पूर्व कैदी हैं। इस बीच, अमेरिका ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार की घोषणा का आकलन कर रहा है और कुछ व्यक्तियों के बारे में उनकी संबद्धता और ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में चिंतित है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अंतरिम सरकार की सूची में विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो तालिबान के सदस्य हैं या उनके करीबी सहयोगी हैं और

इसमें कोई महिला नहीं है। दूसरी ओर, तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार के सदस्यों की आलोचना पर विशेष रूप से अमेरिका के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हमला बोला है, जिसका कहना है कि अंतरिम तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देना दोहा शांति समझौते का उल्लंघन है।

सार समाचार

तालिबान ने 200 अमेरिकियों, अन्य विदेशियों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दी

काबुल। तालिबान ने अमेरिकी प्रशासन के साथ बातचीत के बाद कम से कम 200 अमेरिकी नागरिकों सहित अन्य विदेशियों को अफगानिस्तान छोड़ने की इजाजत दी है। रिपोर्टों के अनुसार, विदेशी नागरिक गुरुवार को चार्टर उड़ानों से काबुल से रवाना होंगे। कतर एयरवेज का एक विमान गुरुवार सुबह काबुल में उतरा, जो अमेरिकी नागरिकों और अन्य विदेशी नागरिकों को ले जाएगा। अगस्त में राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा होने के बाद इस हवाईअड्डे से उड़ान भरने वाला यह पहला अंतर्राष्ट्रीय विमान है। कतर के अधिकारियों ने काबुल हवाईअड्डे पर मीडिया से बातचीत में पुष्टि की कि कतर एयरवेज की उड़ान अफगानिस्तान से जाने वाले विदेशियों को ले जाएगी। कतर के एक अधिकारी ने कहा, काबुल हवाईअड्डा अब पूरी तरह से चालू है। आज कतर के विमान ने दोहा से काबुल के लिए अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी और अब वही चार्टर लड़ाई विदेशियों के साथ होगी। कतर के अधिकारियों के साथ आए तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि वे काबुल हवाईअड्डे को चालू करने के लिए कतर के अधिकारियों के आभारी हैं। उन्होंने कहा, काबुल हवाईअड्डा पूरी तरह से चालू हो जाएगा। हमारे कतरी भाइयों ने पुष्टि की है कि सभी तकनीकी मुद्दों को सुलझा लिया गया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और अंतर्राष्ट्रीय विमान यहां आएंगे।

ब्रिटेन की संसद ने सरकार के नए स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल शुल्क का किया समर्थन

लंदन। ब्रिटेन की संसद ने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) और वयस्क सामाजिक देखभाल सेवाओं के लिए सरकार की नई कर योजना को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार, हाउस ऑफ कॉमन्स ने स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल लेवी का समर्थन करने के लिए 319 से 248 तक मतदान किया, देश भर में श्रमिकों और नियोक्ताओं पर एक नया 1.25 प्रतिशत कर, लाभांश दरों में समान राशि की वृद्धि के साथ, अगले अप्रैल से प्रभावी होगा। कर शुरू में राष्ट्रीय बीमा में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 2023 से यह एक अलग कर बन जाएगा। इस कदम से लाखों लोगों की महामारी और विनाशकारी लागत के कारण होने वाले बैकलॉग से निपटा जाएगा, प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, अगले तीन वर्षों में लगभग 36 बिलियन पाउंड (49 बिलियन डॉलर) जुटाने की उम्मीद है, जो सीधे स्वास्थ्य और पूरे देश में सामाजिक देखभाल के लिए होगा। जॉनसन ने स्वीकार किया कि कोई भी कंजर्वेटिव सरकार कर नहीं बढ़ाना चाहती है और यह घोषणापत्र की प्रतिबद्धता को तोड़ता है। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारर ने आलोचना कि, कर काम करने वाले लोगों पर अनुचित था, जिसका अर्थ है कि न्यूनतम वेतन पर एक देखभाल कार्यकर्ता को कर वृद्धि मिलेगी, लेकिन वेतन वृद्धि नहीं।

केप टाउन ने कोविड पीड़ितों के सम्मान में स्मारक उद्यान खोले

केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी केप टाउन में कोविड -19 महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वालों को समर्पित स्मारक उद्यान और कब्रिस्तानों को खोल दिया गया है। प्रत्येक सर्कल में पेड़ लगाए गए हैं। केप टाउन के मेयर डैन प्लेटो ने बुधवार को एक बयान में कहा कि ये पेड़ जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने निवासियों और कर्मचारियों द्वारा पड़ोस और शहर में किए गए योगदान की याद दिलाएंगे। प्लेटो ने मेनार्डविले पार्क में एक स्मारक उद्यान में लिक्विडम्बर स्टायरसिफ्लुआ के पेड़ लगाने में मदद की। मेयर प्लेटो ने कहा कि हम इन पेड़ों के पोषण के माध्यम से उनका सम्मान करेंगे और मैं इन पौधों को बढ़ता हुआ देखने के लिए उत्सुक हूं। प्लेटो ने सामुदायिक सेवाओं और स्वास्थ्य के लिए मेयरल कमेटी के सदस्य जाहिद बदरूडियन के साथ मिलकर स्मारक उद्यानों में छह कोविड -19 स्मरण समारोह भी आयोजित किए। बदरूडियन ने कहा कि बगीचे उन कई प्रियजनों के लिए जीवित स्मारक हैं, जिन्हें शहर ने खो दिया है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें न केवल आज याद कर रहे हैं, बल्कि जैसे-जैसे ये पेड़ बढ़ेंगे और फलेंगे फूलेंगे, वह उनके जीवन का प्रमाण होगा। उनके अनुसार वृक्षों से बना वृत्त जीवन चक्र का प्रतीक है। नेशनल आर्बर मंथ के लिए स्मारक उद्यान लगाना भी गतिविधियों का हिस्सा है, जो स्थायी पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक विकास, सामुदायिक भागीदारी, गरीबी उन्मूलन और वानिकी में रोजगार सृजन के अवसरों को उजागर करने के लिए एक वार्षिक अभियान है।

हम अफगान मामलों में विदेशियों के हस्तक्षेप को इजाजत नहीं देंगे: मुजाहिद

काबुल । अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के सर्वोच्च नेता मुल्ला हिबतुल्ला अखुंदजादा युद्धग्रस्त देश में नई तालिबान सरकार का नेतृत्व करेंगे। संगठन ने यह घोषणा की है। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने कहा कि समूह अगली सरकार के नाम और ढांचे पर विदेशियों के हस्तक्षेप को खारिज कर देगा। मुजाहिद ने कहा, हम किसी को भी अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। सरकार का नाम, उसका प्रकार और रूप अफगानों का है और वे इस बारे में तय करेंगे। तालिबान ने यह भी कहा कि नई सरकार अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात है। तालिबान के सांस्कृतिक आयोग के सदस्य अनामुल्ला समांगानी ने कहा, अफगानिस्तान में नई सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के नाम से अपना काम शुरू कर दिया है। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और अब्दुल सलाम हनफी को कार्यवाहक उपप्रधान मंत्री नामित किया गया है, जबकि मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब को कार्यवाहक रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आमिर खान मुत्ताकी को कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, और हक्कानी नेटवर्क आतंकवादी समूह के संस्थापक के बेटे सरजुद्दीन हक्कानी को कार्यवाहक गृह मंत्री नामित किया गया है।

गौरवशाली पल! 2 भारतीय शिक्षक वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2019 के लिए चुने गए

लंदन। (एजेंसी)।

बिहार के भागलपुर के गणित के शिक्षक सत्यम मिश्रा और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद की सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी और गणित की शिक्षिका मेघना मुसुनुरी ने बृहस्पतिवार को घोषित इस साल के 10 लाख डॉलर के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए शीर्ष 50 शिक्षकों में जगह बनायी है। 10 लाख डॉलर के वैश्विक शिक्षक पुरस्कार का आयोजन वर्की फाउंडेशन यूनेस्को के साथ मिलकर करता है। इसके लिए 121 देशों से 8,000 से अधिक नामांकन आए। वर्की फाउंडेशन के संस्थापक सन्नी वर्की ने बताया, ''केवल शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही हम अपने कल को सुरक्षित कर सकते हैं। शिक्षा विश्वास के साथ भविष्य का सामना करने की कुंजी है।'' सत्यम मिश्रा ने दुनिया को देखने के बच्चों के तरीके में बदलाव के संकल्प और छात्रों के लिए गणित विषय को रूचिकर बनाने के लिए गुणा के आसान फॉर्मूलों को लेकर इस सूची में जगह बनायी।

मेघना मुसुनुरी को शिक्षा के संदर्भ में भविष्यवादी, परोपकारी और जुनूनी उद्यमी बताया जाता है। वह फाउंटेनहेड ग्लोबल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं और साथ ही उद्यमी महिलाओं को ऑनलाइन मौजूदगी स्थापित करने के लिए उनका मार्गदर्शन करने वाली, गूगल की संस्था '' वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन द वेब'' (डब्ल्यूईओडब्ल्यू) की हैदराबाद शाखा की भी अध्यक्ष हैं। यूनेस्को में शिक्षा के लिए सहायक महानिदेशक स्टेफेनिया गियानिनी ने कहा, ''अगर हमें कोविड-19 के मद्देनजर एक बेहतर दुनिया का पुनर्निर्माण करना है तो हमें हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पैदायशी अधिकार देने को प्राथमिकता देनी होगी।'' इसके साथ ही, पहली बार शुरू किए गए चेगडॉटओआरजी ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार में शीर्ष 50 छात्रों की सूची में चार भारतीय छात्र भी शामिल हैं। इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया, नयी दिल्ली के वास्तुकला के 21 वर्षीय छात्र कैफ अली, आईआईएम अहमदाबाद के 23 वर्षीय एमबीए छात्र आयुष गुप्ता, झारखंड की 17 वर्षीय छात्रा सीमा कुमारी और हरियाणा के केंद्रीय विश्वविद्यालय का 24 वर्षीय छात्र विपिन कुमार शर्मा शामिल हैं। इस पुरस्कार के तहत 1,00,000 डॉलर की धनराशि दी जाएगी। चेगडॉटओआरजी की प्रमुख लीला थॉमस ने कहा, ''कोविड के इस दौर में कैफ, आयुष, सीमा और विपिन जैसे छात्रों ने बड़ी बाधाओं के बावजूद पढ़ाई करते रहने और बेहतर भविष्य के लिए लड़ते रहने का बड़ा साहस दिखाया है।

ईस्टर संडे विस्फोट मामले को यूएनएचआरसी में उठाएगा श्रीलंका का कैथोलिक चर्च

कोलंबो (एजेंसी)।

श्रीलंका के कैथोलिक चर्च ने 2019 ईस्टर संडे बम धमाकों के लिए न्याय करने में सरकार की विफलता के खिलाफ जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) से शिकायत करने का संकल्प लिया है। यूएनएचआरसी तमिल टाइगर विद्रोहियों के खिलाफ तीन दशक लंबे युद्ध के दौरान किए गए कथित युद्ध अपराधों पर श्रीलंका की भी जांच कर रहा है। 13 सितंबर से शुरू होने वाले यूएनएचआरसी के 48वें सत्र में श्रीलंका पर चर्चा होगी। मुख्य पादरी (आर्कबिशप) मैल्कम कार्डिनल रंजीत ने बुधवार को मीडिया से कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय मांगेंगे, क्योंकि सरकार सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। चर्च कैबिनेट के प्रवक्ता की उस घोषणा पर प्रतिक्रिया दे रहा था, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे गुरुवार को इटली जाएंगे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात कर उन्हें बम विस्फोटों की जांच के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें 269 लोग मारे गए थे और 500 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इसने बयान में कहा, सरकार वेटिकन को गुमराह करने और ईस्टर संडे हमले के पीछे की सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही है। इंटरनेशनल स्तर पर पीछे छिपना बचकाना है। कार्डिनल रंजीत ने कहा, हम इस सरकार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय को धोखा देने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जा रही है तो हम अंतरराष्ट्रीय स्तर भी जा रहे हैं। कोलंबो महाधर्मप्रांत के प्रमुख ने खुलासा किया कि उन्होंने वेटिकन को जांच की धीमी गति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया है और वेटिकन ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से जेनेवा में शिकायत करने का बीड़ा उठाया है। हालांकि बुधवार को चर्च के कड़े जवाब के कुछ घंटों बाद, सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री पोप से नहीं मिलेंगे और न ही वेटिकन सिटी जाएंगे। विदेश मंत्री जी. एल. पीरिस ने एक बयान में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने किसी भी स्तर पर अनुरोध नहीं किया है और न ही उन्हें पोप से मिलने के लिए वेटिकन जाने का निमंत्रण मिला है। पिछले महीने, चर्च ने शिकायत की थी कि श्रीलंका के सैन्य बुद्धिजीवियों के एक वर्ग के 2019 के आत्मघाती हमलावरों के साथ संबंध थे, जिनके इस्लामिक स्टेट आतंकी समूह के साथ संबंध

होने का संदेह है। कार्डिनल रंजीत ने सैन्य बुद्धिजीवी और आत्मघाती हमलावरों के बीच एक कथित संबंध के बारे में शिकायत की थी जो कि समन्वित आत्मघाती बम विस्फोटों की श्रृंखला में राष्ट्रपति जांच आयोग (पीसीओआई) के दौरान सामने आया था। कार्डिनल ने यह भी कहा था कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बार-बार तारीख सहित हमले के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की, लेकिन श्रीलंकाई सेना ने नरसंहार को रोकने के लिए कार्रवाई नहीं की।

उत्तर कोरिया ने स्थापना दिवस मनाया, सैनिकों और सैन्य साजो-सामान की निकाली गई परेड

काबुल। (एजेंसी)।

सियोल। उत्तर कोरिया ने देश के 73वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी में 'गूज स्टेप' (विशेष प्रकार का कदमताल) करते सैनिकों और सैन्य साजो-सामान की परेड निकाली। इस परेड की निगरानी राष्ट्र के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन ने की। सरकारी मीडिया ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 'कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी' ने यह भी बताया कि लड़ाकू विमानों ने 'किम इल सुंग स्क्वायर' के ऊपर विशेष बनावट (फॉर्मेशन) में उड़ान भरी।

इस चौराहे का नाम किम के दादा, राष्ट्र के संस्थापक के नाम पर पड़ा है। रोडोंग सिनमन समाचार-पत्र ने किम की एक तस्वीर प्रकाशित की जो क्रीम रंग

का सूट पहने हुए और सैनिकों एवं दर्शकों का बालकनी से अभिवादन करते दिख रहे हैं। खबरों में यह नहीं बताया गया कि किम ने इस कार्यक्रम के दौरान कोई भाषण दिया या नहीं। उत्तर कोरिया अक्सर किम इल सुंग स्क्वायर पर परेड में हजारों हंस-कदमताल (गूज स्टेप) करने वाले सैनिकों और अपने सबसे उन्नत सैन्य साजो-सामान को प्रदर्शित करके राष्ट्र के प्रमुख दिवस मनाता है।

तालिबान का नया फरमान, क्या है विरोध का मकसद, क्या लगेंगे नारे समेत इन बातों की देनी पड़ेगी जानकारी

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

काबुल। अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार का गठन कर लिया है और इसी के साथ ही उन्होंने एक नया फरमान जारी किया है। आपको बता दें कि तालिबान के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और तालिबान की असल सच्चाई सामने आ गई। तालिबान ने नागरिकों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, उनके अधिकारों का हनन होने लगा।

तालिबानी फरमान

तालिबानी सरकार के फरमान के मुताबिक विरोध प्रदर्शन से पहले न्याय मंत्रालय से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। विरोध प्रदर्शन के 24 घंटे पहले इसकी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों (तालिबानी लड़ाकों) को देनी पड़ेगी।

तालिबानी सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन के बाद गृह मंत्रालय ने यह नियम बनाए हैं। अफगानी मीडिया के मुताबिक विरोध प्रदर्शन से पहले उसका मकसद, कहां, कब और कैसे होगा और नारे क्या लगेंगे इसकी जानकारी देनी पड़ेगी।

क्या है विरोध का मकसद ?

काबुल में महिलाओं समेत सैकड़ों प्रदर्शनकारी ने मंगलवार को पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इस दौरान तालिबान ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए गोलीबारी की थी। वहीं प्रदर्शन को कवर कर रहे कई अफगानी पत्रकारों को भी गिरफ्तार किया। हाल ही पत्रकारों को बेरहमी से पीटने की घटना भी सामने आई है। तालिबान ने दो पत्रकारों को बेरहमी पीटा, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लगी आग, कर्मी दल के सदस्यों ने दी धुआं निकलने की खबर

मॉस्को। (एजेंसी)।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के रूसी भाग में बृहस्पतिवार तड़के आग और धुएं का अलार्म बज उठा तथा कर्मी दल के सदस्यों ने धुआं निकलने और प्लास्टिक जलने की गंध आने की सूचना दी। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी 'रोस्कोस्मोस' ने कहा कि यह घटना रूस निर्मित 'ज़्वेज़्दा' मॉड्यूल में तब हुई जब स्टेशन की बैटरी रीचार्ज की जा रही थीं।

रोस्कोस्मोस के मुताबिक, कर्मी दल के सदस्यों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वायु फिल्टर खोल दिए और हवा गुणवत्ता सामान्य होने पर आराम करने लौट गए। एजेंसी ने बताया कि कर्मी दल के सदस्य बृहस्पतिवार को निर्धारित 'अंतरिक्ष वॉक'पर योजना के अनुरूप आगे बढ़ेंगे। इस अंतरिक्ष स्टेशन को वर्तमान में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री मार्क वंदे हेई, शेन किम्ब्रू और मेगन मैक्ऑर्थर तथा रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस के ओलेग नोविस्की एवं प्योत्र दबरोव, जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री अकिहिको होशाइड और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट द्वारा संचालित किया जा रहा है। नोविस्की और दबरोव बृहस्पतिवार को छह घंटे की 'अंतरिक्ष वॉक' करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए होम क्वारंटाइन को दिखाई झंडी

कैनबरा (एजेंसी)।

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने गुरुवार को विदेशों में फंसे नागरिकों से वादा किया कि देश में आने पर होम क्वारंटाइन जल्द ही उपलब्ध होगा। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मॉरिसन ने आस्ट्रेलियाई लोगों द्वारा उठाए गए बहुत भारी बोझ को स्वीकार किया, जो महामारी की शुरूआत के बाद से विदेशों में फंसे हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के अनुसार, मुझे पता है, विदेशों में ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए, यह एक बहुत ही कठिन और निराशाजनक समय रहा है। अब तक, लगभग 38,000 ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों और विदेशों के निवासियों ने स्वदेश लौटने के लिए विदेश मामलों और व्यापार विभाग के साथ पंजीकरण कराया था। मॉरिसन ने पहले विदेशों में आस्ट्रेलियाई लोगों से वादा किया था कि वे दिसंबर 2020 तक घर आ जाएंगे लेकिन कोविड -19 के घरेलू प्रकोप ने होटल संगरोध प्रणाली

को बाधित कर दिया। विपक्ष के नेता एंथनी अल्बनीस ने देरी के लिए प्रधान मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि मॉरिसन ने विदेशों में फंसे आस्ट्रेलियाई लोगों को घर वापस लाने में मदद नहीं किया था। मॉरिसन ने कहा कि सरकार होम क्वारंटाइन को होटल क्वारंटाइन के बजाय आगमन के लिए प्राथमिक विकल्प बनाने के लिए काम कर रही है, जिससे देश में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है गुरुवार की सुबह, ऑस्ट्रेलिया ने कोविड -19 के 1,745 नए स्थानीय रूप से अधिग्रहित मामलों की सूचना दी, जिससे कुल संक्रमण 66,318 हो गया, जबकि मरने वालों की संख्या 1,013 है। नए मामलों में से, 1,405 देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य और महामारी के वर्तमान उपरिकेंद्र न्यू साउथ वेल्स (एनसीडब्लू) से थे, जहां स्वास्थ्य विभाग ने भी पांच मौतें दर्ज कीं। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र (एसीटी) ने 15 नए मामले दर्ज किए, जिससे देश की राजधानी में सक्रिय मामलों की संख्या 227 हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब तक 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 64 प्रतिशत आस्ट्रेलियाई लोगों को कम से कम एक कोरोनावायरस वैक्सीन प्राप्त हुई है। और 39 प्रतिशत को पूरी तरह से टीका लगाया गया है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे चुके अशरफ गनी ने देश छोड़ने के फैसले का किया बचाव

काबुल। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 15 अगस्त को काबुल छोड़ने के अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि देश की राजधानी को खून-खराबे से बचाने के लिए उन्होंने यह रास्ता चुना। गनी ने ट्वीट कर भ्रष्टाचार के व्यापक आरोपों को खारिज किया और दावा किया वह देश से कोई धन साथ नहीं लेकर गए। उन्होंने कहा कि इस मामले की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। गनी के अचानक देश छोड़ने की अफगानिस्तान और कई देशों में व्यापक आलोचना हुई थी। वहीं, अमेरिका ने बातचीत के समझौते से पहले ही तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने और सरकार के पतन के लिए गनी के देश छोड़ने के कदम को जिम्मेदार ठहराया था।

सार समाचार

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद पांच दिवसीय दौरे पर हिमाचल आयेंगे .. परमार व जयराम ठाकुर ने हिमाचल आने का न्योता दिया

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ आज राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की। इस अवसर पर विपिन सिंह परमार ने भारत के राष्ट्रपति को 17 सितम्बर, 2021 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा आने तथा हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्णिम जयन्ती वर्ष पर आयोजित एक दिवसीय विशेष सत्र को सम्बोधित करने का न्योता दिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पांच दिवसीय दौरे पर 16 सितंबर को शिमला पहुंचेंगे और 20 सितंबर तक यहीं रहेंगे। वह शिमला राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में निवास करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 सितंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होंगे। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना था व प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। प्रदेशवासी इस स्वर्णिम वर्ष को संपूर्ण उल्लास और धूमधाम के साथ मना रहे हैं।

यूपी के 250 निजी स्कूलों ने दी आरटीई दाखिले रोकने की धमकी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लगभग 250 गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूलों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के छात्रों को तब तक प्रवेश नहीं देने का फैसला किया है, जब तक राज्य सरकार शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी स्कूलों को देय पिछले तीन वर्षों की फीस नहीं देती है। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन (यूपीएसए) के प्रतिनिधिमंडल ने बुनियादी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी मांगों पर गौर करने के अनुरोध के साथ मुलाकात की, जिसमें विफल रहने पर वे नए शैक्षणिक सत्र 2021-22 से आरटीई के तहत एक भी छात्र को प्रवेश नहीं दे पाएंगे। यूपीएसए के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने कहा, शिक्षा के अधिकार 2009 की धारा 12 (2) और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के तहत, सरकार को आरटीई के तहत छात्रों को प्रवेश देने के लिए स्कूलों को एक निश्चित राशि का भुगतान करना पड़ता है। यह राशि एक वर्ष में प्रति छात्र अपनी कक्षा के अनुसार वास्तविक खर्च है। पिछले तीन वर्षों से सरकार ने आरटीई के तहत छात्रों को प्रवेश देने के लिए निजी स्कूलों को भुगतान नहीं किया है।

करनाल की घटना की जांच के लिए सरकार तैयार: हरियाणा के मंत्री

चंडीगढ़, 9 सितम्बर (आईएएनएस)। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को कहा कि सरकार करनाल में लाठीचार्ज की घटना की जांच के लिए तैयार है, जिसमें एक आईएएस अधिकारी की किसानों के सिर फाड़ने की टिप्पणी शामिल है, जिसके कारण जिला मुख्यालय सचिवालय के बाहर धरना दे रहे किसानों में गुस्सा है। हालांकि, विज स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि बिना जांच के किसी को भी फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि कोई इसकी मांग कर रहा है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, करनाल उप-विभागीय मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा को पहले ही ट्रांसफर कर दिया है, जो पुलिस को निर्देश देते हुए कैमरे में कैद हो गए थे कि अगर वे सुरक्षा घेरा तोड़ते हैं तो विरोध करने वाले किसानों के सिर पर वार करें। किसान 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज का विरोध कर रहे हैं, जिसमें पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया था, जब किसानों ने कथित तौर पर भाजपा की बैठक स्थल की ओर मार्च करने की कोशिश की थी, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अन्य नेताओं के साथ मौजूद थे। विज ने अपने गृहनगर अंबाला में मीडिया से कहा, हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन यह न केवल एसडीएम (आयुष सिन्हा) से संबंधित होगा, बल्कि पूरे करनाल प्रकरण से संबंधित होगा। इस जांच में, यदि किसान या उनके नेता दोषी पाए जाते हैं, तो जो भी कार्रवाई उचित समझी जाएगी वह होगी।

मायावती ने वायरल फीवर और डेंगू पर जताई चिंता, बोलीं, सरकार ध्यान दे

लखनऊ। यूपी में डेंगू के साथ वायरल फीवर लोगों के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री योगी काफी चिंतित थे वह बीते दिनों फिरोजाबाद के दौरे पर भी पहुंचे थे। लेकिन हालात में अधिक सुधार नहीं है। इसे लेकर बसपा मुखिया ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सरकार को इस पर ध्यान देने की अपील की है। बसपा मुखिया मायावती ने गुरूवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि यूपी में कोरोना महामारी के बीच डेंगू व अन्य रहस्यमयी बुखार आदि का प्रकोप भी यहां बड़ी तेजी से लगभग पूरे प्रदेश को अब अपने चपेट में ले रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के अभाव में इनके मरीजों की काफी मौतें भी हो रही हैं, जो अति-चिन्तनीय। सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे। गौरतलब हो कि आगरा मंडल में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप थम नहीं रहा। दिन-ब-दिन स्थिति गंभीर होती जा रही है। फिरोजाबाद जिले में बुधवार को डेंगू-वायरल फीवर से कई बच्चों की मौत हो गई। इसके अलावा मथुरा, आगरा तथा कुछ अन्य जिलों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। मैनपुरी और फरुर्खाबाद में भी डेंगू के काफी मामले सामने आ रहे हैं। उधर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की मानें तो अब मौत के आंकड़ों में काफी कमी आई है। प्रदेश के डीजी हेल्थ ने बताया कि डेंगू की पहचान होने के बाद इलाज की दिशा भी सही है। अब लोग भी गंभीर हुए हैं, लिहाजा सही जगह इलाज हो रहा है।

बाड़मेर में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, बोले- हमने दिया स्पष्ट संदेश, हर चुनौती के लिए भारत तैयार

बाड़मेर। (एजेंसी)।

राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। इस अवसर पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत मौजूद रहे।

इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं विशेष रूप से नितिन गडकरी को बधाई देता हूं। इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड पर हम लोगों को सी-13 के द्वारा उतरने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसमें बैठकर ही हमने सुखद अनुभूति की है। स्मूथ लैंडिंग से पहले वायुसेना प्रमुख हमें बताते रहे हैं कि वहां पर बहुत बढ़िया इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड बना है।

उन्होंने कहा कि आज देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 के युद्ध में हमने जीत हासिल की थी, उसका स्वर्णिम वर्ष भी देश मना रहा है। आज जहां पर खड़े होकर हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 के युद्ध का साक्षी रहा है। ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड मन में उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी विश्वास पैदा करता है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से कुछ दूर पर ही इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना, यह सिद्ध करता है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है।

उन्होंने कहा कि भारत के भीतर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए कूबत है, यह संदेश भी हमने स्पष्ट रूप से दे दिया है। इस दौरान उन्होंने नितिन गडकरी और एनएचएआई को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड महज 19 महीने में तैयार हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमा पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, वायुसेना तैयार रहा है और तमाम थल, जल और वायुसेना पर देश को भरोसा रहा है।

कोरोना मरीज का आया 1.80 करोड़ का बिल, सोमनाथ भारती और मनीष तिवारी ने की कार्रवाई की मांग

नयी दिल्ली।(एजेंसी)।

कोरोना वायरस महामारी के चलते निजी अस्पतालों की मनमानी के मामले सामने आए। राजधानी दिल्ली के मैक्स अस्पताल ने कोरोना के इलाज के लिए एडमिट हुए एक मरीज को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बिल थमा दिया। जिस पर आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सवाल खड़ा किया और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से जरूरी कार्रवाई करने की बात कही।

क्या है पूरा मामला ?

कोरोना संक्रमण से पीड़ित एक मरीज दिल्ली में स्थित मैक्स अस्पताल में 28 अप्रैल को एडमिट हुआ था। जिसे 6 सितंबर को डिस्चार्ज करते हुए अस्पताल ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए का बिल थमा दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक ने अस्पताल से बात की और ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक सोमनाथ भारती के पास एक दिन पहले एक महिला आई थी। जिसने मैक्स अस्पताल में कोरोना से संक्रमित पति के इलाज का बिल दिखाया था, जो 1 करोड़ 80 लाख रुपए का था। जिसे देखकर सोमनाथ भारती चकित रह गए थे। जिसके बाद उन्होंने इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की बात कही थी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से इसकी शिकायत की। वहीं, अस्पताल प्रशासन ने कहा कि मरीज की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर थी। उन्हें मधुमेह की समस्या थी और हाइपरटेंशन था। मरीज के गॉल ब्लाडर में भी दिक्कत थी। अस्पताल ने कहा कि मरीज को जब डिस्चार्ज किया जा गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की समस्या के बारे में हमें जानकारी नहीं दी और वो इलाज से खुश थे।

कैबिनेट ने 56 परिवहन विमानों की खरीद को दी मंजूरी, देश में पहली बार मिलिट्री प्लेन बनाएगी प्राइवेट कंपनी

नयी दिल्ली।(एजेंसी)।

साल 2021 भारत के रक्षा उद्योग के लिहाजे से बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल भारत सरकार की ओर से बहुत सी ऐसी खरीदारी की जा रही है या फिर की जाने वाली है जो मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाई गई हो। वायुसेना को एयरबस के सी-295 मीडियम लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्रॉफ्ट मिलने वाले हैं। सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने एक अहम फैसले में भारतीय वायु सेना के पुराने एवरो बेड़े को हटाने के लिए 56 सी-295 विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार 56 इस तरह के एयरक्रॉफ्ट वायु सेना को मिलेंगे। यूरोप की बड़ी एविएशन कंपनी एयरबस से ये लिए जाएंगे। 56 एयरक्रॉफ्ट में 16 सीधे कंपनी से लिए जाएंगे। जबकि बाकी 40 का भारत में ही निर्माण किया जाएगा। अलावा 40 विमान कंपनी द्वारा भारत में टाटा के साथ एक समूह (कंसोर्टियम)के हिस्से के तहत बनाए जाएंगे।

पुराने पड़ गए एवरो विमान की जगह लेगा

माना जा रहा है कि यह डील 21,000 करोड़ रुपये (लगभग 3 अरब डॉलर) से अधिक की होगी। सी-295एमडब्ल्यू विमान नयी तकनीक के साथ 5 से 10 टन क्षमता वाला परिवहन विमान है जो वायुसेना के पुराने पड़ गए एवरो -748 विमान की जगह लेगा। मंत्रालय ने कहा, करार पर हस्ताक्षर करने के 48 महीनों के भीतर स्पेन से 16 विमानों की उड़ान भरने की स्थिति में आपूर्ति की जाएगी जबकि 40 विमानों का निर्माण करार पर हस्ताक्षर के 10 वर्षों के भीतर टाटा कंसोर्टियम द्वारा भारत में किया जाएगा।

एमएसपी में बढ़ौतरी ऊंट के मुंह में जीरा, कांग्रेस प्रवक्ता बोले- किसानों से धोखा कर रही सरकार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

शिमला ।मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ौतरी किए जाने का प्रचार किया जा रहा है।जबकि यह किसानों के साथ सरासर धोखा है।सरकार मीडिया में इस बढ़ौतरी को ऐसे प्रचारित कर रही है मानों मोदी सरकार ने किसान हित में बहुत बड़ा कदम उठा दिया हो।जबकि हक़ीक़त में यह किसान के साथ धोखा है। यह आरोप हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मोदी सरकार पर लगाए।उन्होंने कहा कि गेहूं में बढ़ौतरी 1975 रुपए प्रति क्विंटल से बढा कर 2015 यानी 2प्र. कि बढ़ौतरी, गन्ना 285 से 290(1.75प्र. बढ़ौतरी), सूरजमुखी5327 से 5441(2.14प्र.) की गई है जो मात्र ऊंट के मुंह में जीरा के समान है।

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महंगाई में बढ़ौतरी 50 से 100त्न तक हो चुकी है।डीज़ल-पेट्रोल के दाम हर माह में दो दो बार बढ़ाए जा रहे हैं।कीटनाशक दवाइयां, ट्रेक्टर के दाम सहित कृषि क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली सेवाएं,औजार सब कुछ महंगा हो चुका है।ऐसे में एक-दो प्रतिशत की बढ़ौतरी करना किसान के साथ मज़ाक है।उन्होंने कहा कि तीन काले कानून को वापस लेने के लिए क्यूंकि किसान पिछले नौ महीनों से प्रदर्शन कर रहा है अतः सरकार ने किसानों को अपमानित करने के उद्देश्य से एमएसपी में यह बढ़ौतरी की है।

दीपक शर्मा ने कहा कि सरकार ज़मीनी हकीकत को देखते हुए किसानहित में व्यवहारिक निर्णय नहीं ले रही है।यह दुर्भाग्यपूर्ण है।देश के किसान को प्रताड़ित, अपमानित करके खेती करने के प्रति हतोत्साहित किया जा रहा है।यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु,बेरोजगारी खत्म करने हेतु कृषि क्षेत्र ही एकमात्र सर्वोत्तम उपाय है।लेकिन सरकार इस क्षेत्र को चन्द निजी बढ़े घरानों को सौंप कर देश के साथ धोखा कर रही है।सरकार के इस नकारात्मक रवैये से देश को दूरगामी दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि किसान विरोधी भाजपा सरकार को देश की जनता सबक सिखाएगी।उन्होंने कहा कि किसान हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी निरन्तर आवाज़ उठाती रहेगी और संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़ी।

असदुद्दीन ओवैसी बोले- मॉब लिंचिंग के नाम पर मारे जा रहे हैं मुसलमान!

लखनऊ।(एजेंसी)।

राजधानी लखनऊ से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित जिला बाराबंकी में वहां के जिला प्रशासन ने एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को जनसभा भले ही न करने की इजाजत दी हो,फिर भी उन्होंने मीडिया से मुलाकात करके अपने मन की बात कह ही दी। ओवैसी ने कहा कि हम केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश में एक मजबूत पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। एआइएमआइएम नेता ने कहा कि 2014 से मॉब लिंचिंग के नाम पर केवल मुसलमानों को मारा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी आज बाराबंकी के मुस्लिम बाहुल्य कटरा मुहल्ले में आए थे। वह यहां पार्टी की युवा शाखा के जिलाध्यक्ष चौधरी फैज उर-रहमान के आवास पर चाय पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा कर रहे थे। यहीं पर उन्होंने मीडिया से भी बात की।

गौरतलब हो कि जिला प्रशासन द्वारा पहले ओवैसी की जनसभा और मीटिंग कार्यक्रम रद किए जाने बाद बुधवार की देर शाम कुछ शर्तों के साथ एआइएमआइएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी की युवा शाखा के जिलाध्यक्ष चौधरी फैज उर रहमान के आवास पर सिर्फ चाय-नास्ता कराने की अनुमति प्रदान कर दी गई थी। यह और बात थी कि ओवैसी को सिर्फ पचास लोगों के साथ चर्चा की अनुमति दी गई थी,लेकिन इस आदेश का पालन जरा भी नहीं हुआ। ओवैसी को सुनने और देखने के लिए अच्छा-खास हुजूम उमड़ पड़ा था। इस दौरान मास्क और कोविड नियमों का पालन भी होता नहीं दिखा। ओवैसी का दौरा शांति पूर्वक निपटने से प्रशासन रे राहत की सांस ली है क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू एक्शन सेना भारत की ओर से एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के जिले में प्रवेश करने का विरोध करने की घोषणा की गई थी। प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण युवजन सभा व राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंद एक्शन सेना विकास मिश्रा का इससे संबंधी एक पोस्टर भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसके दृष्टिगत प्रशासन हलकान था।

तालिबान पर मेरे बयान को जानबूझकर तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया: महबूबा

श्रीनगर।(एजेंसी)।

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के यह कहने के एक दिन बाद कि तालिबान असली इस्लामिक शरिया का पालन करता है, दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है, उन्होंने गुरुवार को साफ किया कि उनके बयान को जानबूझकर तोड़-मरोड़ किया गया।

ट्विटर पर उन्होंने लिखा, आश्चर्य की बात नहीं है कि शरिया पर मेरे बयान को जानबूझकर तोड़ा-मरोड़ा गया है। शरिया को कायम रखने का दावा करने वाले अधिकांश देश इसके वास्तविक मूल्यों को आत्मसात करने में विफल रहे हैं। उन्हें केवल क्या करें और क्या ना करें, ड्रेस कोड आदि के जरिए महिलाओं पर प्रतिबंध लगाना आता है। असली मदीना चार्टर पुरुषों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकारों को निर्धारित करता है। वास्तव में महिलाओं को संपत्ति, सामाजिक, कानूनी और विवाह अधिकार दिए गए हैं। गैर-मुसलमानों के पास धार्मिक स्वतंत्रता और कानून की समानता के समान अधिकार हैं जो धर्मनिरपेक्षता का सार है। उन्होंने आगे कहा, हजरत खदीजा तुल कुबरा, पैगंबर एसडब्ल्यूए की पहली पत्नी एक स्वतंत्र और सफल व्यवसायी महिला थीं। हजरत आयशा सिद्दीकी ने ऊंट की लड़ाई का नेतृत्व किया और 13000 सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया। इस्लामी इतिहास मुक्ति और सशक्त महिलाओं के ऐसे उदाहरणों से भरा है। लेकिन ऐसे समय में जब भारत इतना ध्रुवीकृत हो गया है। इस्लामफोबिया बढ़ रहा है और अफगानिस्तान संकट ने इसे और खराब कर दिया है। मुसलमानों से हमेशा यह साबित करने की अपेक्षा की जाती है कि वे हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। मैं देख सकती हूं कि इस धारणा को आगे बढ़ाने के लिए मेरे बयान का इस्तेमाल किस वजह से किया जा रहा है। बुधवार को महबूबा ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा कि अपने पहले कार्यकाल में तालिबान की छवि मानवता और मानवाधिकारों के खिलाफ थी। इस बार अगर वे अफगानिस्तान पर शासन करना चाहते हैं, तो उन्हें पवित्र कुरान में दिए गए वास्तविक इस्लामी शरीयत का पालन करना चाहिए जो अधिकारों को निर्दिष्ट करता है। पैगंबर द्वारा दिए गए मदीना के मॉडल के अनुसार महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग और शासन करते हैं।

दिल्ली में भी कर सकेंगे चारों धाम के दर्शन, देश के दार्शनिक स्थलों का भी संगम होगा पंजाबी बाग का पार्क

नई दिल्ली (एजेंसी)।

राजधानी दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में सौंदर्यीकरण का काम लगातार तेजी से चल रहा है। पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भी सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी है। यहां रहने वाले 25 वार्डों के 10 से 12 लाख लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल, इस महीने के अंत तक पंजाबी बाग के पास बन रहे भारत दर्शन पार्क का काम पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही पंजाबी बाग के वेस्ट पार्क में एक साथ भारत के कई दर्शनीय स्थलों का आप दीदार कर सकेंगे। इस पार्क में इन दर्शनीय स्थलों को बनाया जा रहा है। उसका काम लगभग पूरा होने वाला है।

इस परियोजना की देखरेख करने वाले एक अधिकारी ने बताया कि यहां चार धाम यानी कि बद्रीनाथ, द्वारिका, पूरी और रामेश्वरम की आकृतियां तैयार की गई हैं और उसे पार्क में खड़ा किया जा रहा है। यहां एक वटवृक्ष भी तैयार किया गया है और साइड बेस पर रखा गया है। कुल मिलाकर देखें तो आकृतियां लगभग तैयार हो चुकी है। सिर्फ उन्हें उनके स्थान पर स्थापित करने का काम बाकी रह गया है। हालांकि जिस एजेंसी को यह काम करने के लिए दिया गया है उसका दावा है कि अगले 10 से 15 दिनों में इसे पूरा कर लिया।

अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल के प्रतिरूप को हटाने के बाद उसकी जगह उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ, गुजरात के द्वारका धाम, ओडिशा स्थित जगन्नाथ पुरी और तमिलनाडु स्थित रामेश्वरम मंदिर के प्रतिरूप को तैयार किया गया है। जिस जगह गोल्डन टेंपल था वहां अब वटवृक्ष है। चारों धाम के प्रतिरूप मीनाक्षी टेंपल के आस पास ही बने हैं। इन प्रतिरूपों को लगभग 160 वर्ग मीटर के दायरे में बनाया गया है और प्रत्येक की ऊंचाई 20 से 25 फीट है। पाक का थीम विविधता में एकता है जो देश के प्रतिष्ठित स्मारकों जैसे चारमीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, नालंदा खंडहर, मैसूर पैलेस, मीनाक्षी मंदिर, हवामहल, हंप्टी खंडहर, विक्टोरिया मेमोरियल, साँची स्तूप जैसे ऐतिहासिक इमारतों को प्रदर्शित करता है।

पार्क, जो 14 राज्यों से प्रतिकृतियों की मेजबानी करेगा, मार्च-अप्रैल 2021 तक पूरा होने की उम्मीद थी। लेकिन कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर, मानसून और स्वर्ण मंदिर प्रतिकृति पर विवाद से निर्माण कार्य में देरी हुई। पार्क छह एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और इसकी शुरुआती अनुमानित लागत लगभग 18-20 करोड़ रुपये थी। सराय काले खां में वेस्ट टू वंडर पार्क के बाद, भारत दर्शन पार्क दूसरा ऐसा पार्क होगा, जिसमें कबाड़ सामग्री से तैयार स्मारकों की प्रतिकृतियां होंगी।

आईएसआई जम्मू-कश्मीर को अस्थिर करने आईएसकेपी कैडर को पीओके भेज रहा : इंटेल

नई दिल्ली (एजेंसी)।

जम्मू-कश्मीर पर अपनी नापाक नजर रखते हुए पाकिस्तान की खुफिया शाखा -इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) के कैडर को पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) में भेज रहा है। नवीनतम खुफिया सूचनाओं के अनुसार, ये आईएसककेपी कैडर हाल ही में अफगानिस्तान की जेलों से रिहा हुए थे और पाकिस्तान लौट आए थे और अब आईएसआई ने घाटी में अपने आतंकी एजेंडे को अंजाम देने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने खुलासा किया है कि कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने आईएसकेपी कमांडर मुंशीब की आवाजाही और उपस्थिति पर नजर रखी है, जो कथित तौर पर इस उद्देश्य के लिए विभिन्न आतंकी संगठनों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह पिछले कुछ महीनों से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। केरल के लगभग 25 युवा हाल ही में अफगानिस्तान गए हैं और आईएसकेपी कैडर में शामिल हुए थे, अब इनपुट आ रहे हैं कि आईएसआई केरल के उन कट्टरपंथी युवाओं का इस्तेमाल भारत में हमले करने के लिए कर सकती है, सूत्रों ने आगे कहा, उनकी गतिविधियां एजेंसियों की रडार पर है।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सुरत के पाडेसरा क्षेत्र में चोरी करने आये चोर ने पकड़े जाने के डर से किया हत्या

एक घर में घुसकर लूटे और दो भाइयों में से एक का गला पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी

क्रांति समय दैनिक समाचार

सूरत के मणिनगर, पांडेसरा में आधी रात को एक अजनबी ने चोरी की नीयत से एक घर में घुसकर दो भाइयों में से एक का गला काट कर घर से

युवक की मौत के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी।

रुपये नकद लूट लिए. हत्या की सूचना मिलने के बाद से फरार है। आधी रात को चोर के घुसने की जानकारी होने पर जब वह दोनों भाइयों को पकड़ने गया तो चोर ने जानलेवा हमला कर दिया। बृजेश ने कहा कि एक की मौत हो गई और दूसरा हाथ में घायल हो गया।

बृजेश गुप्ता (मृतक के भाई) ने कहा कि मृतक अपने घर के पास पान-मसाला का कारोबार कर रहा था । 3 भाइयों में सबसे छोटे वीरेंद्र कुमार जमना प्रसाद गुप्ता (Age-21) थे। बुधवार की आधी रात को कोई चोरी की नीयत से घर में घुस गया। चोर की बात सुनकर वीरेंद्र और विष्णु दोनों चोर को पकडने के लिए दौड़े। चोर ने वीरेंद्र को गर्दन पर और विष्णु को हाथ में घायल कर दिया और मेरे घर से रुपये नकद लेकर भाग गया।

हमले के बाद विष्णु ने जब धमाका किया तो पूरा परिवार जाग उठा । वीरेंद्र को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देख वह चिचियारी से बाहर भागी। वीरेंद्र को अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब विष्णु को टांके लगाकर छुट्टी दी गई। जांच शुरू हुई। फिलहाल हमलावर लुटेरे

(मृतक की फाइल फोटो)

पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच की।

सह हत्यारे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पांडेसरा पुलिस आगे की जांच कर रही है।

सूरत में एटीएम से पैसे निकालने वाला यूपी गैंग गिरफ्तार

क्रांति समय दैनिक समाचार

सूरत समेत कई इलाकों में एटीएम मशीनों से पैसे निकालने में मदद करने के बहाने अंतरराज्यीय गिरोहों ने पासवर्ड चोरी करने वाले एटीएम कार्ड बदलने वाले खातों से पैसे निकालने की पहल की है. साइबर क्राइम पुलिस ने विभिन्न आरोपियों के पास से 17 एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और 38,870 रुपये की नकदी जब्त की है और छह से अधिक मामलों को सुलझाया है.

धोखाधड़ी का दावा करने में मदद

, पुलिस ने कहा, पिछली कुछ बार एटीएम मशीनें सबसे गरीब लोगों को निशाना बना सकती हैं, लोगों के एटीएम कार्ड चोरी करने के लिए एटीएम मशीन से पैसे निकालने जा रहे हैं, पैसे निकालने जा रहे हैं, लोगों की मदद करने के लिए एक कैबल बनाया जब वे किसी भी परेशानी में हैं उनके खाते खाली गैज उसके खिलाफ कई शिकायतें थीं। गैग को गति देने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया था। एसओजी की जांच में सामने आया कि ऐसे सभी अपराधों में शामिल

गिरफ्तार आरोपी

(1) शिवमसिंघा उर्फ चंचल ठाकुर सुरसिंह रजवाड़ी 21 राहेविनायकनगर, शहर के बगल में संदीपभाई गणपत तिवारी इंडोर्स गोवलका रोड पांडेसरा सूरत समाहा मूल गांव, थाना थंडिया जिप्रयागराजा, (यूपी)

(2) ऋतिक उर्फ भोले सुरेंद्र बहादुर सिंह यूवी 19 व्यवसाय निष्क्रिय मकान नंबर ३ गंगोत्रीनगर बमरोली रोड पांडेसरा सूरत

(3) अमित उर्फ धर्मेंद्र पंजाब सिंह यूवी पांडेसरा सूरत मूल गांव समाहा थाना थांडिया जिला प्रयागराज, (यूपी)

गिरोह की प्रक्रिया एक जैसी थी। इसलिए एसओजी की टीम ने अलग-अलग टीमों का गठन कर मानव संसाधन व तकनीकी निगरानी के आधार पर जांच शुरू की।

मुद्दमाला सहित नकदी कब्जे

में लेकर जांच के दौरान खुफिया जानकारी मिली है कि इस तरह के अपराध गिरोह के सदस्यों ने फिर से फिरकामं पाांडेसरा महादेव नगर सोसायटी में फिर से अपराध किया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को दौड़ा लिया। जिसके पास से पुलिस को अलग-अलग बैंकों के एटीएम कार्ड नंबर 17, मोबाइल फोन नंबर 3 और 38870 रुपये नकद बरामद हुए और कुल 68870 रुपये बरामद हुए.

जापान के महावाणिज्य दूत डॉ. यासुकाता ने की राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात

क्रांति समय दैनिक समाचार

अहमदाबाद। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत से गुरुवार को जापान के मुंबई में नवनियुक्त महावाणिज्य दूत डॉ. फूकहोरी यासुकाता ने

शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने जापान के महावाणिज्य दूत का राजभवन में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान जापान के महावाणिज्य दूत ने गुजरात के सर्वांगीण विकास यात्रा की प्रशंसा की। इस मौके पर राज्यपाल ने फूकोहोरी यासुकाता को स्मृति चिह्न भी भेंट किया।

गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर राज्यपाल की शुभकामनाएं

क्रांति समय दैनिक समाचार

गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रतने गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर राज्य के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राज्यपालश्रीने अपने शुभ संदेश में कहा है कि, विघ्नहर्ता गणेशजी का यह पर्व श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी पर्व संसार में सुख, शांति, समृद्धि और भ्रातृभाव को और सुदृढ बनायेगा।

कपड़ा के क्षेत्र में दक्षिण गुजरात के सूरत, तापी और नवसारी जैसे जिलों में भारी निवेश की संभावना है।

सूरत और दक्षिण गुजरात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएलआई योजना का अधिकतम लाभ उठा सकेंगे:चैंबर

क्रांति समय दैनिक समाचार

सूरत,कैबिनेट में हुई बैठक में कैबिनेट ने एमएमएफ टेक्सटाइल्स और टेक्निकल टेक्सटाइल्स को कवर करने वाले १३ सब-डिवीजनों के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। चैंबर के अध्यक्ष ने कहा कि उद्योगपति लंबे समय से योजना की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और भारत सरकार द्वारा योजना के तहत 10,683 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है.

इसमें से करीब 7,000 करोड़ रुपये एमएमएफ टेक्सटाइल सेक्टर को और 4,000 करोड़ रुपये टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर को आवंटित किए गए हैं। शुरुआत में यह योजना केवल परिधान और परिधान क्षेत्र के लिए थी। चैंबर ने प्रधानमंत्री से संपर्क किया और योजना के तहत एमएमएफ कपडे के उत्पादन को शामिल करने का अनुरोध किया। आज, जब योजना की घोषणा की गई है और चैंबर द्वारा प्राप्त विवरण, यह कहना सुरक्षित है कि एमएमएफ कपड़े को भी योजना में शामिल किया गया है।

इस पीएलआई योजना के

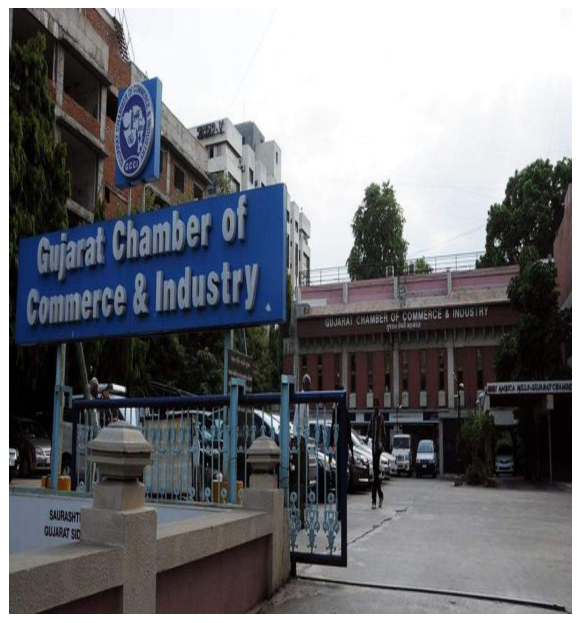

तहत नया निवेश करने वाली इकाइयों को 21 मार्च, 2023 से पहले आवेदन करना होगा और इकाइयों को दो साल में अपने निवेश की लागत से कम से कम दोगुना कारोबार करना होगा और 31 मार्च, 2025 तक उत्पादन शुरू करना होगा। योजना को योजना-1 और योजना-2एम में विभाजित किया गया है।

योजना-1 में अधिकतम 15% एवं न्यूनतम 11% प्रोत्साहन तथा योजना-2 में न्यूनतम ७त्न एवं अधिकतम 11% प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, एकीकृत कपड़ा क्षेत्र में कम से कम 60% मूल्यवर्धन किया जाना है और स्टैंड अलोन स्वतंत्र इकाई द्वारा कम से कम 30% मूल्यवर्धन किया जाना है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो इकाइयां आरओएसटीसीएल / आरओडीटीईपी जैसी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, वे इस योजना के अलावा पीएलआई योजना का लाभ उठा सकेंगी। यदि हम दोनों योजनाओं के लाभों को मिला दें, तो कपड़ा इकाइयों को उनके टर्नओवर के मुकाबले 21 प्रतिशत का नकद रिफंड मिल सकता है। इसके अलावा, तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में, भारत वर्तमान में विशेष यार्न के लिए पूर्ण आयात पर निर्भर है। इसलिए इस योजना के आने से विशेष सूत का उत्पादन भी बढ़ेगा, जो भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाएगा।

वर्तमान में पूरी दुनिया चीन +1 रणनीति के तहत योजना बना रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ इस योजना के शुरू होने के बाद दक्षिण गुजरात में कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्योगों को बड़ी संख्या में मिलने की संभावना है। चैंबर ने योजना के तहत एमएमएफ कपड़े को कवर करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कपड़ा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय कपड़ा और रेल मंत्री दर्शन जरदोश को धन्यवाद दिया।

चैंबर के उपाध्यक्ष हिमांशु बोडावाला ने कहा कि दक्षिण गुजरात, विशेष रूप से सूरत जिला, एमएमएफ वस्त्रों के उत्पादन में 65% का योगदान देता है। इस योजना के लागू होने के बाद एमएमएफ टेक्सटाइल के क्षेत्र में सूरत जिले का योगदान काफी बढ़ सकता है। कहा जा रहा है कि यह योजना टियर-3 शहरों में निवेश को बढ़ावा देगी।

इस योजना के तहत सूरत, तापी और नवसारी जैसे दक्षिण गुजरात के जिलों में भारी निवेश की संभावना है।

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार
में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार
संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

समस्या आपकी हमें भेजे

अपने क्षेत्र में समस्याएं
हमें लिखे या बताएँ
और समस्याएं का हल
संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180
या फोटा,वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरों
और अन्य शहर,ग्राम में पत्रकारों
की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते है
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com